RNI No. DELMUL/2012/47011

31 जुलाई, 2026 शुक्रवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 120

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से अच्छा फिल्डर बना : रैना 07

संक्षिप्त वार्ता

ई-20 पर सरकार ने स्वीकारा: पुरानी बीएस-3 गाड़ियों के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं प्रभावित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है कि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल के उपयोग से कुछ पुरानी बीएस-3 (बीएस-3) वाहनों के कुछ पुर्जों पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि

इससे इंजन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता और वाहन के इंजन में किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2005 से 2016 के बीच निर्मित कुछ बीएस-3 मानक वाले वाहनों में ई-20 ईंधन के उपयोग से रबर के कुछ पार्ट्स और गैस्केट प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पुर्जे सामान्य सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदले जा सकते हैं और इसके लिए किसी बड़े तकनीकी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। गडकरी ने कहा कि उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों में ई-20 ईंधन के उपयोग से वाहनों की कुल कार्यक्षमता (परफॉर्मेंस) या टिकाऊपन (ड्यूरेबिलिटी) पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया है।

देशभर में बारिश का कहर

उत्तराखंड-जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड, श्रद्धालुओं की यात्रा रुकी

वेब वार्ता, नई दिल्ली

देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राजस्थान सहित 16 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन की घटनाओं के कारण सड़क संपर्क बाधित हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अलर्ट हैं।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में गुरुवार सुबह कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण केदारनाथ ट्रैकिंग मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग के सिल्ली क्षेत्र में मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ समय के लिए बाधित रहा, जबकि पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी से गिरे विशाल बोल्डर

केदारनाथ मार्ग बंद, 16 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव से जनजीवन प्रभावित

की चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव के बीच गंगाजल भरने उतरा एक युवक नदी में बहने लगा। मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी क्षेत्र और कुपड़ा गांव के पास भी भारी बोल्डर और मलबा सड़क तक आ गया, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई।

स्कूल की दीवार ढही

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के चलते एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की दीवार ढह गई। वहीं अक्रमल क्षेत्र में भूस्खलन के बाद कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी।

कई गांव नदी के कटाव की चपेट में

उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी के कटाव ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। सौ से अधिक परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं और दो मकान नदी में समा चुके हैं। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर घटने के बावजूद कटान तेज हो गया है, जिससे कृषि भूमि और पेड़ नदी में बह रहे हैं।

भारी बारिश का अलर्ट जारी

इधर, मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सकुर्लेशन और शियर जोन जैसे तीन मजबूत मौसम तंत्र प्रभावी होने से उज्जैन, सागर सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

बाब-अल-मंडेब से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की तैयारी

वेब वार्ता, सना। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री घेराबंदी की घोषणा के एक सप्ताह बाद अब दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर टोल लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। यदि यह योजना लागू होती है तो इससे वैश्विक समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर व्यापक असर पड़ सकता है। हालांकि हूती समूह ने इस प्रस्ताव पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा या समय-सीमा जारी नहीं की है।

बताया जा रहा है कि हूती नेतृत्व बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अधिकांश व्यावसायिक जहाजों से शुल्क वसूलने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। बाब-अल-मंडेब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है, जो दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसी मार्ग से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ी मात्रा में तेल, गैस और अन्य वस्तुओं का समुद्री परिवहन होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का नया शुल्क या बाधा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग लागत को प्रभावित कर सकती है। 20 जुलाई को हूती समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इसके बाद क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों पर हमलों और समुद्री गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि समूह इस रणनीति के जरिए क्षेत्रीय संघर्ष में अपना दबाव और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

शुल्क लगाने हुई चर्चा

रिपोर्टों के अनुसार, इस महीने की शुरूआत में हूती संगठन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ईरान गए थे, जहां उनकी ईरानी अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। इन बैठकों में कथित तौर पर बाब-अल-मंडेब जलमार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही ईरान या हूती नेतृत्व ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि चीनी जहाजों को संभावित शुल्क से छूट दी जा सकती है, ताकि वे इस मार्ग से बिना किसी बाधा के गुजर सकें। हालांकि इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

चिंता बढ़ने की आशंका

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर केवल सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा। यह मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य का एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। ऐसे में दोनों समुद्री मार्गों पर किसी भी प्रकार का तनाव अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति, माल ढुलाई और वैश्विक बाजार में कीमतों की अस्थिरता बढ़ा सकता है। इससे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की चिंताएं भी बढ़ने की आशंका है।

जवान निडर होकर करें कर्तव्य का पालन बाकी जिम्मेदारी मेरी

वेब वार्ता, नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने जवानों को निडर होकर कर्तव्यों का पालन करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से लिए गए फैसलों और की गई कार्रवाई की जिम्मेदारी वह स्वयं लेंगे। सीआरपीएफ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित

करते हुए महानिदेशक ने कहा कि चाहे ऑपरेशनल बटालियन हो या कानून-व्यवस्था संभालने वाली इकाई, सभी जवान बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां भी जवाबदेही तय करने की आवश्यकता होगी, उसकी जिम्मेदारी वह निदेशक जनरल के रूप में स्वयं स्वीकार करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है, जबकि जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए अपनाई गई रणनीति की आंतरिक समीक्षा चल रही है। प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल में तीन लोगों के घायल होने के बाद इस कार्रवाई पर सवाल उठे थे।

पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और शासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

बागेश्वर धाम की पहल: 365 बेटियों के विवाह का लिया संकल्प

वेब वार्ता, छतरपुर

प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण और अनूठी घोषणा की। उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम अब देश का ऐसा पहला तीर्थस्थल बनेगा, जहां साल के 365 दिनों में 365 जरूरतमंद बेटियों का कन्या विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की बेटियों का विवाह कराना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विवाह का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। इस अवसर पर बागेश्वर धाम परिसर में आठ महावीर शिलाओं का भी विधिवत

अनावरण और स्थापना की गई, जिससे धाम की आध्यात्मिक महत्ता और बढ़ गई है। यह धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

शास्त्री ने दावा किया कि जो लोग नकारात्मक ऊर्जा या मानसिक परेशानियों से ग्रसित हैं, उन्हें अब इधर-उधर भटकने या तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके अनुसार, बालाजी के चरणों से ही पूर्ण लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, आज बागेश्वर धाम पर आठ महावीरों की शिला की स्थापना हुई है। जो भी नकारात्मक या नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं, उन्हें दुनिया में तांत्रिक-मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी के चरणों से ही पूर्ण लाभ मिलेगा। यह बयान उन लोगों के लिए आशा का संदेश है जो विभिन्न मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिला की स्थापना को लेकर बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया, बागेश्वर धाम पर स्थापित हुए अष्टवीरों की तांत्रिक शिला विश्वभर के तांत्रिक विद्या से ग्रस्त लोगों को मिलेगी बालाजी की कृपा एवं पुण्य लाभ। यह पोस्ट उन दावों को पुष्ट करता है कि इन शिलाओं में विशेष शक्तियाँ हैं जो नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकती हैं।

...लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस पहल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और विश्व का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम बन गया है, जहां 365 दिनों में 365 बेटियों का कन्या विवाह कराया जाएगा। यह घोषणा बागेश्वर धाम को न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र बल्कि एक प्रमुख सामाजिक सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने आगे कहा कि बागेश्वर धाम में स्थापित आठ महावीर शिलाएं भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनेंगी और इनसे लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा।

खैबर पख्तूनख्वा में डीएसपी समेत सात पुलिसकर्मी मारे गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) एक बार फिर बड़े चरमपंथी हमले से दहल उठा है। हंगू जिले के खजीना बांदा पुलिस चेकपोस्ट पर हुए इस भीषण हमले में कम से कम सात पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिनमें एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) भी शामिल हैं। यह घटना पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है, जहां चरमपंथी समूह लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बड़ी संख्या में हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाते हुए अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस हमले में 22 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पीएम मोदी ने बांग्लादेशी पीएम रहमान को भेजा न्योता

ढाका। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के दिल्ली दौरे पर सस्पेंस बना हुआ है। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता बांग्लादेश के पीएम को भेजा है। इस सवाल पर क्या तारिक रहमान भारत आएंगे, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि ये फैसला खुद बांग्लादेश के पीएम ही करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह तारिक रहमान के भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दौरा जल्द हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री खलीकुर रहमान और राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम के साथ बैठक के बाद दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बातचीत का माहौल अच्छा था। उन्होने कहा कि खेल और क्रिकेट सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: आरोपी के सरकारी मकान से मिले मंदिर के कीमती उपहार व नकदी

वेब वार्ता, देहरादून

उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी मामले में जांच तेज हो गई है। एसआईटी को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। टीम ने मुख्य आरोपी और बदरी-केदार मंदिर समिति के पूर्व वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल के बदरीनाथ स्थित सरकारी आवास से मंदिर के कीमती चीजें और भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। जांच टीम आरोपी प्रमोद को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर बदरीनाथ पहुंची थी, जहां उसकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। बरामदगी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है, ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे।

एसआईटी ने बदरीनाथ स्थित नीलकंठ वीवीआईपी गेस्ट हाउस की पहली मंजिल पर बने आरोपी प्रमोद नौटियाल के सरकारी आवास का ताला खुलवाकर तलाशी ली। जांच में कमरे से मंदिर से जुड़े बेशकीमती उपहार और 500-500 रुपए के नोटों की भारी नकदी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कुबूल किया कि वह कुछ सामग्री अपने साथ ले गया था। अब एसआईटी बरामद सामान और दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बदरीनाथ में

कार्रवाई के साथ ही एसआईटी की दूसरी टीम ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित प्रमोद नौटियाल के निजी आवास पर भी छापेमारी की। यहां से संपत्तियों, बैंक खातों और आर्थिक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी रकम को संपत्तियां खरीदने या अन्य निवेशों में इस्तेमाल किया गया है।

अन्य लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है

रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया है कि बदरीनाथ मंदिर में 2 जुलाई तक दानपात्रों की 34 बार गिनती की गई, जिसमें करीब 36 करोड़ रुपए की नकदी दर्ज की गई थी। शुरूआती चरण में करीब 23 करोड़ रुपए की गणना पूरी हो चुकी थी। एसआईटी अब 21 जून के बाद की सीसीटीवी फुटेज, दान गिनती प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था की जांच कर रही है1 सवाल यह भी उठ रहा है कि लगातार निगरानी के बावजूद हेराफेरी कैसे होती रही। चढ़ावा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर्मचारी, भंडार प्रभारी, वरिष्ठ सहायक और लेखा लिपिक समेत कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। चमोली पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमोद से मिली जानकारी के आधार पर अन्य संदिग्ध ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

घायल के इलाज का आदेश देकर बोला सुप्रीम कोर्ट

असाधारण परिस्थितियों में कर सकते पैलेट गन का इस्तेमाल

वेब वार्ता, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों, विशेषकर पैलेट गन के छर्रों से जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों के इलाज का निर्देश रेखा गुप्ता सरकार को दिया है। शीर्ष अदालत ने इस दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहाना भी शामिल थे, ने दिल्ली बीजेपी सरकार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि

घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा मिले। यह आदेश 20 जुलाई को पेपर लीक के विरोध में सीजेपी के बैनर तले संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में आया है। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) द्वारा हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद और पैलेट से घायल हुए दो अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर गौर किया, जिसमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धातु वाले पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग हुई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के परामर्श का हवाला देकर कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह 20 जुलाई को सीजेपी की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के उपयोग से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। याचिकाकताओं ने आरोप लगाया है कि घटना में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग घायल हुए और एक छात्र की आंखों की रोशनी चली जाने का आरोप है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका में सभी घायलों के लिए उचित मुआवजा, समुचित चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास की भी मांग की गई है।

जिस वर्ग को कॉकरोच कहकर अपमानित किया, वे जेन-जी युवा हैं: उद्धव ठाकरे

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जेन-जी और खासकर कॉकरोच की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज की नई पीढ़ी को कॉकरोच कहकर खारिज किया जा रहा है, ठीक उसी तरह मुगलों ने भी मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को चूहा कहा था। उद्धव ने कहा कि यदि युवाओं को कॉकरोच कहा जाएगा, तो उनका नाराज होना स्वाभाविक है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लगभग 13 से 28 साल की आयु वाले जिस वर्ग को कॉकरोच कहकर अपमानित किया गया, वे वास्तव में जेन-

जी श्रेणी के युवा हैं। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी केवल 17 साल के थे जब उन्होंने तोरणा किला जीता था और संत ज्ञानेश्वर ने भी बेहद कम उम्र में ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। उद्धव ने आगे कहा कि जिन्हें कॉकरोच कहकर अपमानित किया गया, वे उसी वर्ग से आते हैं जिसे अब हम जनरेशन जी कहते हैं, जिनकी उम्र करीब 13-14 से 27-28 साला के बीच है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि आवाज उठाने और अन्याय के खिलाफ बोलने पर आज के युवाओं को छोटा या कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। बता दें उद्धव ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब संसद के चल रहे मॉनसून सत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने भाषणों के दौरान जेन-जी की शब्द और स्लैंग्स का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार के सुधारों का बचाव करने वाले सत्ता पक्ष के सदस्यों से लेकर नीट विवाद पर सरकार को घेरने वाले विपक्षी सांसदों तक सभी ने सोशल मीडिया पर मशहूर इन शब्दों का बहसों में इस्तेमाल किया है।

संपादकीय

भूमि की फर्जी खरीद

जमीनों की खरीद में एक पूरा माफिया सक्रिय है और धारा 118 के सीधे उल्लंघन के निशान लिए पूरा पहाड़ा भरभरा रहा है। मामला गगल एयरपोर्ट के साथ और भी संगीन हो गया जब जम्मू से आकर बसा परिवार सौ कनाल जमीन पर हिमाचली घोषित हो गया। आश्चर्य यह कि जहां चंद मरले जमीन की खरीद मुश्किल है, वहां जम्मू से आए दंपती ने सौ कनाल पर कब्जा जमा लिया। पूरे प्रदेश में भूमि बिक्री के कई हॉट स्पॉट बने हैं, तो इसलिए कि एक पूरा तंत्र विकसित हो गया है। जाहिर है यह भू-राजस्व विभाग की मिलीभगत और राजनीतिक प्रश्रय के बिना असंभव है। यहां लैंड सीलिंग कानून के बाद पैदा हुए लैंड लार्ड्स की उत्पत्ति का भी एक लंबा सिलसिला रहा है।

शहर बड़े हुए, लेकिन शहरीकरण अंगीकार नहीं हुआ। खेत बिकते रहे, लेकिन कृषि बचाने के कानून नहीं बने। मुजारा कानून के तहत लघु जमींदार खत्म हुए, लेकिन जिन्हें जमीनें मिली, वे सौदा करते रहे। इसी तरह नौतोड़ जमीनों का आबंटन भी कृषि उपज के बजाय भूमि के सौदों का जरिया बन गया। सामाजिक उत्थान के इरादों से आए लैंड सीलिंग एक्ट ने जमीनों की बिक्री खोल दी। नतीजतन कांगड़ा घाटी, कुल्लू वैली, हमीरपुर, मंडी तथा बिलासपुर के कृषि योग्य खेत कंक्रीट उगाने लगे। अगर जमीनें छीनीं गईं, तो शर्त यह होनी चाहिए थी कि इनका उपयोग खेतीबाड़ी के लिए ही होगा। जमीनों की बिक्री दरअसल कृषि-बागबानी के प्रति घटता मोह भी है। वन संरक्षण अधिनियम की कमजोरी के कारण भी मानव गतिविधियों का भावार्थ बदल गया है।

बंदर व वन्य प्राणियों के कारण खेतों पर कृषि बंद हो गई और बागीचे ठूंठ बन गए। व्यापारिक गतिविधियों में स्वरोजगार की तलाश के कारण और पर्यटन के अंधाधुंध प्रसार के कारण भी जमीनों की बिक्री का माफिया पैदा हो गया। पर्यटन जिस तरह पहाड़ की ओर चढ़ रहा है, उससे भूमि की बिक्री अब जलस्त्रोतों के नजदीक, जल रिसाव के पास तथा ढांग पर होने लगी है। यही वजह है कि मनाली, कसौली, डलहौजी, मकलोडगंज, नयनादेवी, कुल्लू, मंडी व अन्य अनेक शहरों के नीचे बिक रही जमीनें, इनके वजूद को बर्बाद कर रही हैं। जाहिर है इस स्थिति के लिए शहरी विकास विभाग, ग्राम एवं नगर योजना विभाग, भू-राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा राजनीतिक संस्थाएं दोषी हैं। शहरीकरण के सांचे में गगल एयरपोर्ट का विकास भू-माफिया की ताकत बन जाता है, लेकिन हिमुडा को नए शहर बसाने की फुर्सत नहीं मिलती। पहले चैतड़ू के पास सेटेलाइट टाउन बसाने की योजना राजनीतिक कारणों से बर्बाद हुई, फिर नरघोटा में एक नए शहर की संभावना को समाप्त किया गया। नरघोटा में टाउनशिप के लिए मांग का जबरदस्त आधार था, लेकिन पूरी परियोजना को शहीद कर दिया गया। अगर भू-माफिया की पड़ताल हो तो राजनीति के कई चेहरे, ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही के कई हाथ, ठेकेदारों की पूरी जमात तथा टीसीपी के उल्लंघन करते कई लोग सामने आ जाएंगे। हिमाचल को भू-माफिया से बचाने की राजनीतिक इच्छा तब ही जाहिर होगी अगर पूरे प्रदेश को टीसीपी कानून के तहत लाया जाए, आवासीय व्यवस्था के तहत नए शहर, नई बस्तियां बसाई जाएं तथा लैंड पूलिंग के तहत गैर कृषि योग्य जमीन तथा वन भूमि को भी लाया जाए। शहरों के दायरे तथा विकास के मुहानों पर नवनिर्माण को प्रतिबंधित करके कुछ हद तक बचाव होगा, वरना हिमाचल में जमीनों की खरीद-फरोख्त का धंधा फलता- फूलता रहेगा। इसलिए एयरपोर्ट, मंदिर, मेडिकल कालेज तथा संस्थानों की स्थापना के साथ नव विकास के पूरे क्षेत्र को साडा घोषित करना चाहिए।

पेपर लीक पर राजनीति से नहीं बनेगी बात

देश में जब भी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है तो सबसे पहले लाखों युवाओं के वर्षों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है और विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करता है। प्रदर्शन होते हैं इस्तीफों की मांग उठती है और कुछ समय बाद कोई नया मुद्दा सामने आते ही पूरा विवाद धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जिस मूल समस्या ने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया था उसका स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया है।

हाल के घटनाक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी राजनीतिक दबाव और छात्र आंदोलन के बीच हुआ। सरकार ने इसे परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया निर्णय माना तो विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसी मंत्री के इस्तीफा देने भर से पेपर लीक की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि उत्तर नहीं है तो फिर देश को केवल राजनीतिक घटनाक्रम पर नहीं बल्कि व्यवस्था में व्यापक सुधार पर ध्यान देना होगा।

पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है। पिछले दो दशकों में देश के अनेक राज्यों में शिक्षक भर्ती पुलिस भर्ती पटवारी भर्ती मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। यह भी सत्य है कि अलग-अलग समय में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसलिए इस समस्या को केवल किसी एक दल या एक व्यक्ति की विफलता बताना वास्तविकता से आंखें मूंदने जैसा होगा।

यूपीए सरकार के समय भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगे थे। बाद के वर्षों में भी विभिन्न राज्यों में अनेक भर्ती परीक्षाएं विवादों में रहीं। राजस्थान इसका प्रमुख उदाहरण रहा है जहां शिक्षक भर्ती परीक्षाओं सहित कई मामलों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उस समय भी जिम्मेदारी तय करने को लेकर राजनीतिक विवाद हुए लेकिन व्यवस्था में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं पूरी तरह रुक सकें।

आज भी लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य से पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पेपर लीक अब कुछ व्यक्तियों की शरारत नहीं बल्कि संगठित अपराध का रूप ले चुका है। इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर छपाई परिवहन परीक्षा केंद्र और डिजिटल माध्यमों तक कई स्तरों पर अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय रहता है। करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन के कारण यह एक लाभकारी आपराधिक कारोबार बन चुका है। जब तक इस पूरे नेटवर्क को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक केवल छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे राजनीतिक परिस्थितियां अपनी जगह हो सकती हैं। छात्र आंदोलन विपक्ष का दबाव और चुनावी समीकरण भी किसी लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हुआ कि देश का युवा अब पारदर्शिता और जवाबदेही चाहता है। वह केवल आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहता है। यही कारण है कि पेपर लीक का मुद्दा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि रोजगार और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया।

यह भी ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी आंदोलन बहुत तेजी से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले सकता है। विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की प्रतिक्रियाएं हों या विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन यह लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा है। लेकिन किसी भी आंदोलन या उसके पीछे की परिस्थितियों को लेकर बिना ठोस प्रमाण के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में तथ्यों के आधार पर ही चर्चा और निर्णय होने चाहिए।

पेपर लीक की सबसे बड़ी कीमत वह विद्यार्थी चुकाता है जिसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया होता है। किसी गरीब परिवार का छात्र कोचिंग की फीस भरने के लिए कर्ज लेता है। अनेक अभ्यर्थी उम्र सीमा के अंतिम अवसर का इंतजार करते हैं। परीक्षा रद्द होने पर उनका समय धन और मानसिक संतुलन तीनों प्रभावित होते हैं। इसलिए पेपर लीक केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है।

अब समय आ गया है कि सरकारें इस समस्या को सामान्य अपराध की तरह नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य पर हमला मानें। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित होने तक प्रत्येक चरण पूरी तरह तकनीकी निगरानी में हो। डिजिटल एन्क्रिप्शन सुरक्षित डेटा प्रबंधन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और हर स्तर पर जवाबदेही तय करना आवश्यक है। परीक्षा प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी स्पष्ट हो और किसी भी लापरवाही पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सिर्फ कानून बना देना भी पर्याप्त नहीं होगा। यदि मुकदमे वर्षों तक चलते रहेंगे तो अपराधियों में भय नहीं रहेगा। आवश्यकता ऐसे विशेष न्यायिक तंत्र की है जो पेपर लीक के मामलों की समयबद्ध सुनवाई करे और दोष सिद्ध होने पर शीघ्र सजा सुनिश्चित करे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है उनके लिए भी उचित राहत और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा। जब वे विपक्ष में होते हैं तब पेपर लीक को युवाओं के भविष्य का प्रश्न बताते हैं और सत्ता में आने पर वही समस्या दोबारा सामने आ जाती है। यदि सभी दल इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सहमति बनाएं तो एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था विकसित की जा सकती है जिस पर पूरे देश को विश्वास हो।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना हो सकती है लेकिन इसे अंतिम समाधान मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। यदि आने वाले वर्षों में भी प्रश्नपत्र लीक होते रहे तो स्पष्ट होगा कि समस्या किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में है। इसलिए चेहरा बदलने से अधिक जरूरी व्यवस्था बदलना है।

देश की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा है। यदि युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली से उठ गया तो उसका प्रभाव केवल रोजगार पर नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि पेपर लीक को राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय राष्ट्रीय चुनौती मानकर उसका स्थायी समाधान खोजा जाए। सरकार चाहे किसी भी दल की हो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि मेहनत करने वाले विद्यार्थी को न्याय मिले और बेईमानी करने वालों को कठोर दंड। जिस दिन यह विश्वास स्थापित हो जाएगा उसी दिन पेपर लीक का कारोबार कमजोर पड़ने लगेगा। देश के युवाओं को इस्तीफों से अधिक निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था चाहिए। यही समय की मांग है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।

लेखक - कांतिलाल मांडोत
(वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार-स्तम्भकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

शिक्षा, पढ़ाई और अनुभव से आती है, कोचिंग या ट्यूशन से नहीं?

पिछले तीन दशक से भारत की शिक्षा पद्धति में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया है। प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी जगह ट्यूशन और कोचिंग का एक नया जाल बुना गया है। इस जाल में फंसने के बाद बच्चों को रटन्तु विद्या तो हासिल हो जाती है, परीक्षा में उनके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने पढ़कर हासिल किया है, उसका अनुभव नहीं आने पर ऐसा ज्ञान उनके कोई काम नहीं आता है। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु राह दिखाता है। उसमें चलना शिष्य को पड़ता है। जब तक शिक्षा का ज्ञान अनुभव में ना आए, तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। भारत में 1990 के बाद से एक ऐसा नया दौर शुरू हुआ है, जहां माता-पिता बच्चों को परीक्षा में मिले नंबरों से उनका आकलन करते हैं, यह ठीक नहीं है। हर बच्चे की बुद्धि अलग-अलग होती है। उसके सोचने का तरीका अलग होता है। उसका काम करने का तरीका अलग होता है। माना जाता है, ईश्वर ने हर जीव में अलग बुद्धि और अलग कौशल प्रदान किया है, जो समय और अनुभव के साथ आगे बढ़ता है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई में पहले थ्योरी के साथ-साथ प्रेक्टिकल पर भी ध्यान दिया जाता था। मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को विविधता के साथ ज्ञान उपलब्ध हो, इसके लिए स्कूलों में तरह-तरह की पढ़ाई और अनुभव से बच्चों को जोड़कर रखा जाता था। पिछले 30 वर्षों में जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आया है, उसमें हम रटंतू तोता तैयार कर रहे हैं। कोचिंग से शिक्षा लेने वाले छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर परीक्षा के बाद बहुत ज्यादा नंबर लेने, मेरिट में आने के बाद भी, जब उन्हें अनुभव नहीं मिलता है। परीक्षा के प्रवेश नहीं मिलता है, तो उनके ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह बात परीक्षार्थियों, उनके माता-पिता और अभिभावकों को समझनी होगी। हर बच्चे का पारिवारिक स्तर अलग होता है। उसके घर और परिवार में अलग-अलग तरीके का माहौल होता है। हर परिवार की जीवन शैली अलग होती है। सामाजिक जीवन में विकास के लिये भाषा और गणित का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान समय में तकनीकी ज्ञान भी बड़ा आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल तकनीकी और कंप्यूटर आदि की जानकारी वर्तमान समय में जरूरी हो गई है। इसके लिए प्राथमिक जानकारी एवं उसका उपयोग बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति का भाषा ज्ञान और विज्ञान उसके काम आता है, जो उसकी जरूरत में सदैव बना रहता है। अनुभव और समय की मांग के आधार पर वह अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाता रहता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। अनुभव और समय के अनुसार नया ज्ञान हासिल करना जरूरत है। उसी ज्ञान के सहारे वह आगे बढ़ता चला जाता है। प.पू. आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे, बिल्ली जिस पंजे से शिकार करती है, उसी पंजे से अपने बच्चों का पालन भी करती है। जिसका शिकार करती है, उसे नुकसान होता है। उसी पंजे से बच्चों का पालन होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज यह भी कहते थे, 50 शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव का ज्ञान दोनों बराबर होते हैं। शास्त्रों में लिखा गया ज्ञान यदि अनुभव में नहीं आया है, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है।

पिछले कुछ दशकों में सरकार ने जिस तरह की शिक्षा नीति बनाई है। उसमें नंबरों को आधार बनाकर बौद्धिक ज्ञान को नकार दिया गया है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई में हर जगह अभ्यास के आधार पर परीक्षायें आयोजित हो रही हैं। परीक्षा में अधिक नंबर लाने के लिए ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों की संख्या और उनका प्रभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 60 और 70 के दशक में विश्वविद्यालय में फर्स्ट डिवीजन के नंबर आने पर गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सौभाग्य मिल जाता था। अब 95 फीसदी अंक लाने के बाद भी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश अथवा चयन होता है। जिस तरह पहले पहाडे को याद करा दिया जाता था। उसका उपयोग हमेशा होता था। बच्चों ने जो पहाडा, जोड़-घटाना, गुणा-भाग प्राइमरी में पढ़ा है, सारे जीवन वह याद रहता है। उसी ज्ञान के सहारे वह अपने करियर को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह भाषा का ज्ञान हिंदी मातृ भाषा और अंग्रेजी का ज्ञान आज भी उनके लिए उपयोगी है, जो उन्होंने प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ा था। उच्च शिक्षा में आने के बाद जो ज्ञान हासिल हो रहा है, उसमें डिग्री तो मिल जाती है। जब उस डिग्री के ज्ञान का कोई उपयोग, अनुभव में नहीं आता है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। बच्चों और युवाओं के कई महत्वपूर्ण साल शिक्षा प्राप्त करने में खत्म हो जाते हैं। परिवार के लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं। रोजगार, नौकरी तथा भविष्य को लेकर ठन-ठन गोपाल वाली स्थिति बनी हुई है। दुनिया में जो तकनीकी कई दशकों में ईजाद हुई है उसके लिए कोई विशेष पढ़ाई करने की जरूरत कभी नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने सोच लिया, हमें यह ज्ञान हासिल करना है, उसने हासिल करके ही अपनी पहचान बनाई है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें सोचना होगा आज का वर्तमान कल का भविष्य बनेगा। भारत में इस समय युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। बच्चों की जनसंख्या घटना शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, तो शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना पड़ेगा। हर मस्तिष्क का उपयोग उसकी क्षमता और अनुभव के आधार पर हो। तभी स्वयं को परिवार और देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा का महत्व है। वर्तमान में चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन ने 12 हजार से अधिक रोजगार मूलक डिग्री शुरू की है। भारत में गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की चर्चा होती है। जिस शिष्य को गुरु ने स्वीकार नहीं किया, उसी शिष्य ने द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया। आस्था- विश्वास और अभ्यास से उनके परम शिष्य अर्जुन से आगे निकल गए। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य का अंगूठा मांगना पड़ा। गुरु पूर्णिमा के अवसर ज्ञान के सभी गुरुओं को शत-शत प्रणाम।

लेखक- सनत जैन

राष्ट्रहित में नियमित सैन्य भर्ती जरूरी

राष्ट्र की सुरक्षा केवल आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, अनुशासित, प्रेरित और राष्ट्रनिष्ठ सैनिकों से सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत की सैन्य भर्ती व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सेना को दीर्घकाल तक सक्षम बनाए, युवाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य प्रदान करे तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। समय की मांग है कि सरकार, सेना और रक्षा विशेषज्ञ चिंतन करें।

जून 2026 के अंतिम सप्ताह में देश के विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों से अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा में रहे। प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटते इन युवा सैनिकों का गांवों और शहरों में जिस आत्मीयता और सम्मान के साथ स्वागत हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। कहीं माता-पिता अपने बेटे को सैनिक की वर्दी में देखकर भावुक हुए, तो कहीं फूलमालाओं और बैंड-बाजों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इन दृश्यों ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि भारतीय समाज में सैनिक केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा, अनुशासन और त्याग का प्रतीक हैं। इन भावनात्मक दृश्यों के साथ अग्निपथ योजना को लेकर एक गंभीर बहस भी तेज हुई। प्रश्न यह है कि क्या चार वर्ष की संविदा आधारित भर्ती व्यवस्था भारत की दीर्घकालीन सुरक्षा आवश्यकताओं और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के अनुरूप है, अथवा इसमें आवश्यक सुधारों का समय आ गया है? भारत सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को मंजूरी दी और 16 जून 2022 को इसकी घोषणा की। इसके अंतर्गत 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। पहले वर्ष लगभग 30 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो चौथे वर्ष तक लगभग 40 हजार रुपए हो जाता है। वेतन का 30 प्रतिशत भाग सेवा निधि में जमा होता है, जिसमें सरकार भी समान राशि का योगदान देती है।

सेवा अवधि पूरी होने पर लगभग 11.7 लाख रुपए की कर-मुक्त सेवा निधि, लगभग 48 लाख रुपए का जीवन बीमा तथा कौशल प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को प्रदर्शन, योग्यता और रिक्तियों के आधार पर नियमित सेवा में रखा जाना है, शेष 75 फीसदी अग्निवीरों को 4 साल बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनके करियर और स्थायी रोजगार को लेकर भारी अनिश्चितता रहना तय है, दूसरे चार साल बाद बाहर होने वाले जवानों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा, आजीवन पेंशन या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो पहले स्थायी सैनिकों को मिलती थीं। कई राज्य सरकारों ने पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है तथा निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियों ने भी उन्हें रोजगार देने में रुचि दिखाई है। योजना के इन सकारात्मक पक्षों के बावजूद अनेक रक्षा विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उनका मानना है कि आधुनिक सैनिक तैयार करने की प्रक्रिया केवल हथियार चलाने का प्रशिक्षण नहीं है। सामरिक सोच, नेतृत्व क्षमता, रेजिमेंटल परंपराओं, टीम भावना, मानसिक दृढ़ता और युद्धक्षेत्र में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने में कई वर्ष लगते हैं। इसलिए चार वर्ष की सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम मानी जानी चाहिए। आज भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां पहले से कहीं अधिक जटिल हैं। उत्तरी सीमा पर चीन के साथ तनाव, पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद, ड्रोन के बढ़ते खतरे, साइबर हमले और तकनीक आधारित युद्ध ने सैन्य तैयारियों का स्वरूप बदल दिया है। ऐसे समय में सेना को ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है जो आधुनिक तकनीक के साथ-साथ लंबा व्यावहारिक अनुभव भी रखते हों। रेजिमेंटल भावना भी भारतीय सेना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। यह केवल प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि वर्षों तक साथ सेवा करने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और आपसी विश्वास से विकसित होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि चार वर्ष की सेवा अवधि इस भावना को किस सीमा तक प्रभावित करेगी, इसका आकलन दीर्घकालिक अनुभव और सैन्य अध्ययनों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अग्निपथ योजना के पहले बैच का कार्यकाल वर्ष 2026 में पूरा हो रहा है। कुछ समाचारों में यह भी कहा गया है कि तीनों सेनाएं प्रशिक्षित अग्निवीरों की अधिक संख्या को नियमित सेवा में बनाए रखने के पक्ष में हैं, क्योंकि वे आधुनिक हथियारों, ड्रोन और डिजिटल युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि इस विषय में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में यह उचित होगा कि चार वर्षों के अनुभव का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए और यह देखा जाए कि योजना अपने मूल उद्देश्यों यथा- युवा सेना, सैन्य दक्षता, वित्तीय संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा को किस सीमा तक पूरा कर पाई है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियां स्थायी नहीं होतीं। यदि व्यावहारिक अनुभव यह संकेत दें कि किसी नीति में सुधार की आवश्यकता है, तो समयानुकूल परिवर्तन करना ही दूरदर्शिता है। इसलिए अग्निपथ योजना का मूल्यांकन केवल भावनाओं या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य दक्षता, आर्थिक व्यवहार्यता और युवाओं के दीर्घकालीन भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि समीक्षा से यह स्पष्ट हो कि नियमित सैनिक भर्ती व्यवस्था सेना की युद्ध क्षमता, रेजिमेंटल परंपराओं और युवाओं के हितों के लिए अधिक उपयुक्त है, तो उसे पुन: प्राथमिकता देने या अग्निपथ योजना में आवश्यक सुधार करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

राष्ट्र की सुरक्षा केवल आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, अनुशासित, प्रेरित और राष्ट्रनिष्ठ सैनिकों से सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत की सैन्य भर्ती व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सेना को दीर्घकाल तक सक्षम बनाए, युवाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य प्रदान करे तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। समय की मांग है कि सरकार, सेना और रक्षा विशेषज्ञ मिलकर अग्निपथ योजना के अनुभवों की व्यापक समीक्षा करें और जो भी निर्णय लें, वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकों के मनोबल तथा देश के भविष्य को ध्यान में रखकर लें। यही एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा।

अनुज आचार्य, लेखक बैजनाथ से हैं

आलेख

योजनाओं की पहुँच से बदल सकती है गांव की तस्वीर

किसी भी गांव का विकास केवल सड़क, बिजली या भवनों के निर्माण से नहीं मापा जा सकता। असली विकास तब दिखाई देता है जब गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, आयु या आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो, सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। जब किसी महिला को प्रसव के समय इलाज के लिए दर-दर न भटकना पड़े, जब किसी किशोरी को केवल पानी भरने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े।

जब किसी बुजुर्ग को पेंशन पाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और जब किसी गरीब परिवार को राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े, तभी यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाएं अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंची हैं। दुर्भाग्य से आज भी बिहार के अनेक ग्रामीण इलाकों में योजनाओं और जरूरतमंद लोगों के बीच एक बड़ी दूरी बनी हुई है।

सरकार हर वर्ष ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, आवास, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं लागू करती है। कागजों पर ये योजनाएं गांव के हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का वादा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें ये तक मालूम नहीं होता कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं। कई लोग जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर पाते, तो कई लोग दस्तावेजों की कमी, तकनीकी परेशानियों या प्रशासनिक लापरवाही के कारण लाभ से वंचित रह जाते हैं। सबसे अधिक नुकसान उन लोगों को होता है जिनकी आवाज पहले से ही कमजोर है, जैसे गरीब महिलाएं, किशोरियां, विधवाएं, दिव्यांग व्यक्ति, भूमिहीन मजदूर और समाज के हाशिए पर रहने वाले परिवार।

यदि गांव में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचने लगे, तो गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं और किशोरियों के जीवन में दिखाई देगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों का सबसे बड़ा हिस्सा निभाती हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। वे पानी लाने से लेकर खाना बनाने, बच्चों की देखभाल, पशुपालन और खेतों में काम तक हर जिम्मेदारी निभाती हैं, फिर भी उन्हें अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। यदि उन्हें योजनाओं की जानकारी, उन तक पहुंच और उनका लाभ मिलने लगे, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने परिवार तथा समुदाय में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।

किशोरियों के जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि शिक्षा, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोषण, स्वास्थ्य, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास जैसी योजनाएं पूरी ईमानदारी से लागू हों, तो बहुत-सी लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ने के बजाय उच्च शिक्षा तक पहुंच सकेंगी। उन्हें कम उम्र में विवाह के दबाव से भी राहत मिलेगी, क्योंकि शिक्षा और आर्थिक अवसर उन्हें अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने का साहस देंगे।

ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सभी परिवारों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं। एक गरीब महिला की समस्याएं केवल गरीबी तक सीमित नहीं होतीं। यदि वह भूमिहीन भी है, अशिक्षित भी है, बच्चों की देखभाल भी करती है और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय से भी आती है, तो उसके सामने कई स्तरों की कठिनाइयां होती हैं। ऐसे परिवारों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए केवल समान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए विशेष प्रयास करने होंगे। जिन लोगों को सबसे अधिक जरूरत है, उन्हें सबसे पहले और सबसे सरल तरीके से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यही किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।

यदि हर पात्र परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुरक्षित घर मिले, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे, हर महिला को उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, हर गर्भवती महिला को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और हर जरूरतमंद परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले, तो गांव में गरीबी, कुपोषण, बीमारी और असमानता स्वतः कम होने लगेगी। इससे महिलाओं का समय और श्रम भी बचेगा। जो समय वे पानी लाने या ईंधन जुटाने में लगाती हैं, उसी समय का उपयोग वे आजीविका, शिक्षा, स्वयं सहायता समूहों या अन्य सामाजिक गतिविधियों में कर सकेंगी। इससे परिवार की आय बढ़ेगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी मजबूत होगी।

इसके लिए केवल सरकार की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं है। पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह, विद्यालय, स्थानीय सामाजिक संगठन और गांव के नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक गांव में समय-समय पर 'जागरूकता एवं अधिकार शिविर' आयोजित किए जाने चाहिए, जहां सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाए। पात्रता की जांच, दस्तावेज बनाने, आवेदन भरने और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो।

विशेष रूप से उन परिवारों की सूची तैयार की जाए जो अब तक किसी योजना से नहीं जुड़े हैं। घर-घर जाकर उनसे संवाद किया जाए और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाए। किशोरियों और महिलाओं के लिए अलग संवाद सत्र आयोजित किए जाएं ताकि वे बिना संकोच अपनी समस्याएं साझा कर सकें और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।

साथ ही, गांव स्तर पर सामाजिक निगरानी की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठकों में योजनाओं की प्रगति सार्वजनिक रूप से साझा की जाए। लाभार्थियों की सूची खुली हो, शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो और स्थानीय समुदाय स्वयं यह सुनिश्चित करे कि किसी पात्र व्यक्ति को केवल जानकारी, पहचान, जाति, आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रभाव के अभाव में वंचित न रहना पड़े। जब समुदाय स्वयं योजनाओं की निगरानी करेगा, तब पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।

आज आवश्यकता केवल नई योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि जो योजनाएं पहले से मौजूद हैं, उनका लाभ गांव के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुंचे। दरअसल, योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल बजट और आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि गांव का सबसे कमजोर और सबसे पीछे छूटा व्यक्ति कितना आगे बढ़ पाया है? यही वह रास्ता है जो एक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव को मजबूत बना सकता है।

प्रियंका कुमारी
(यह लेखिका की निजी राय है)

संक्षिप्त वार्ता

एसएफआई पदाधिकारी आइशी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में एसएफआई की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

स्टुडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) वाम दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की छात्र ईकाई है। अदालत में घोष के पेश होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी विजयश्री राठौर ने घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिए। इससे पहले बुधवार को, अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। घोष के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उनकी मुवक्किल सुनवाई की पिछली तारीख पर पेश नहीं हो सकी थीं। यह मामला घोष के खिलाफ 2021 में बाराखंबा रोड पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।

दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गिरोह जुड़े नाबालिग सहित दो पकड़े गए

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में अपराध शाखा की टीम के साथ मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गिरोह के एक संदिग्ध सदस्य और एक किशोर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ रोहिणी के सेक्टर 29 के पास तब हुई, जब एक पुलिस टीम ने स्कूटर पर खेड़ा खुर्द की ओर से आ रहे दो लोग को रुकने का इशारा किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा गोली चलाने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई और कुछ देर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अधिकारी ने कहा कि दोनों संदिग्ध कथित तौर पर हिमांशु भाऊ गिरोह से जुड़े हुए हैं।

बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे यात्री से करीब नौ किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग (कस्टम्स) ने बैंकॉक से दिल्ली आए एक यात्री के पास से 8.961 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) बरामद किया है। मामले में यात्री को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार, एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर 29 जुलाई को बैंकॉक से फ्लाइट टीजी-323 से दिल्ली पहुंचे यात्री को ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। उसके सामान की एक्स-रे जांच में संदिग्ध तस्वीरें दिखाई देने पर विस्तृत तलाशी ली गई। जांच के दौरान बैग से वैक्यूम-सील किए गए पांच पैकेट मिले, जिनमें हरे रंग का संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा था।

कांवड़ यात्रा: अधूरे सेवा शिविर और जर्जर सड़कें बनीं चुनौती

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। सावन में पूर्वी दिल्ली से गुजरने वाले कांवड़ यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिवभक्तों के लिए लगाए जाने वाले सेवा शिविरों की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। वहीं, जर्जर सड़कें यात्रा को जोखिम भरा बना रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी पूर्वी दिल्ली के विभिन्न मार्गों पर श्रद्धालुओं को विश्राम और जलपान की सुविधा के लिए कांवड सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इस साल इन शिविरों की तैयारियों में काफी देरी देखी जा रही है। कई स्थानों पर टेंट तक नहीं लगाए गए हैं। पानी और बिजली अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। श्रद्धालुओं को आराम और जलपान जैसी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। प्रशासन के दावे जमीनी हकीकत से दूर दिख रहे हैं। दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, जीटी रोड, शाहदरा और मंडोली रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं। कुछ जगहों पर सड़क की ऊपरी परत भी उखड़ चुकी है। नंगे पैर या साधारण चप्पलों में चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ते चोटिल होने का कारण बन रहे हैं।

22 में से पांच नालों का काम पूरा, डीजेबी ने दी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने यमुना में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने का काम तेज किया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि 22 चिह्नित नालों में से पांच का काम पूरा हो चुका है। डी-1, डी-2, एडी-2, एडी-8 और पंत नगर/लाजपत नगर नालों का मलजल सीधे यमुना में नहीं जा रहा है। एडी-3 और एडी-4 पर 25 फीसदी काम पूरा है, लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 है। सड़क कटिंग की अनुमति न मिलने से एडी-9, एडी-10 और एडी-13 पर काम रुका है।

फायर एनओसी के बिना 43 कक्षा चलाने वाले स्कूल को नोटिस

सरकारी अधिग्रहण का प्रस्ताव

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

निदेशालय द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे, वित्तीय अनियमितताएं तथा प्रशासनिक उल्लंघन सामने आए हैं। निदेशालय ने स्कूल से अगले सात दिनों में जवाब मांगा है।

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूल का तत्काल अधिग्रहण करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध टिन-शेड संरचनाएं निर्मित की गई थीं। यहां बिना अनुमति भूजल का दोहन किया जा रहा था, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था, अभिभावकों से मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही थी।

वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं का संचालन बिना वैध मान्यता के किया जा रहा था। कुछ कक्षाओं में केवल एक ही निकास द्वार था। आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

निरीक्षण में ये खामियां मिलीं

- अग्नि सुरक्षा एवं भवन निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताएं
- विद्यालय के पास केवल 39 कमरों के लिए फायर एनओसी उपलब्ध थी, जबकि परिसर में 82 कमरों का संचालन किया जा रहा
- बिना अनुमति 30 कमरों वाला विशाल टिन-शेड, एक अवैध बेसमेंट तथा तीसरी मंजिल का भी निर्माण किया
- परिसर में बिना किसी वैधानिक अनुमति के बोरवेल संचालित किया जा रहा था
- विद्यालय की वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की अस्थायी मान्यता 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं का संचालन।

युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल हाउस से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च निकाला।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

प्रदर्शन के दौरान उदय भानु चिब ने कहा कि छात्रों पर कथित बल प्रयोग के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि छात्रों पर पैलेट गन और घातक बल का इस्तेमाल गृह मंत्री के निर्देश पर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और यदि उनकी जानकारी के बिना ऐसा हुआ है तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस छात्रों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री की मौजूदगी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें सदन में आकर इस मामले पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।

आंदोलन जारी रहेगा

युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने, मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। संगठन ने कहा कि मांगें पूरी होने तक उसका आंदोलन जारी रहेगा।

तेहखंड व ओखला में कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट्स की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच तेहखंड और ओखला में 800 टीपीडी क्षमता वाले कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट्स की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इन प्लांट्स में अलग किए गए जैविक कचरे से बायो-गैस बनाई जाएगी। इससे दिल्ली में मौजूद कचरे के पहाड़ कम होंगे, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा और हमारा स्वच्छ दिल्ली का संकल्प और मजबूत होगा।

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत तेखंड एवं ओखला में अत्याधुनिक सीबीजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रतिदिन लगभग 800 टन गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

यह पहल लैंडफिल पर निर्भरता कम करने, प्रदूषण में कमी लाने तथा दिल्ली में आधुनिक एवं प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल दिल्ली के निर्माण के संकल्प को नई गति प्रदान करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एरोसिटी को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकसित करें: एलजी

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को एरोसिटी का दौरा कर यहां चल रहे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एरोसिटी के विस्तार में केवल आधुनिक इमारतों और व्यावसायिक विकास पर ही नहीं, बल्कि जलभराव से बचाव, जल संरक्षण, हरित अवसंरचना और बेहतर यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

दौरे के दौरान जीएमआर के अधिकारियों ने एरोसिटी में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने टिकाऊ शहरी विकास की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र की योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयार की जा रही वर्षाजल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की भी समीक्षा की और इसे मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

शहरी स्वरूप देने में मदद मिलेगी

एलजी ने कहा कि एरोसिटी हवाई अड्डे के निकट होने के कारण लगातार व्यावसायिक और आतिथ्य गतिविधियों का केंद्र बन रही है। ऐसे में यहां बढ़ते यातायात को देखते हुए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और मेट्रो की निर्बाध लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और जीएमआर के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। कहा कि द्वारका और एरोसिटी, दोनों दिल्ली के भविष्य के प्रमुख विकास केंद्र हैं। यदि दोनों क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित किया जाए तो राजधानी को विश्वस्तरीय शहरी स्वरूप देने में मदद मिलेगी।

जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत: दिल्ली सरकार ने मुकदमे नहीं बढ़ाने का लिया फैसला

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार ने जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों में शामिल लोगों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल आम नागरिकों के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल या दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस फैसले को स्थिति सामान्य बनाने तथा नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

सरकार के अनुसार, यह राहत केवल उन लोगों के लिए है जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सरकार ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुरूप जिन व्यक्तियों के विरुद्ध पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस निर्णय का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

सरकार के फैसले का लाभ उन प्रदर्शनकारियों को भी मिलेगा जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार या हिरासत में लिया था। संबंधित मामलों की समीक्षा कर बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की रिहाई की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी। अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन में भाग लेने के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भविष्य में नई दंडात्मक कार्रवाई या नया मुकदमा शुरू करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार ने इस पूरे प्रकरण को अब आधिकारिक रूप से समाप्त मानते हुए कहा है कि सामान्य नागरिकों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

1 अगस्त को लगेगा एनडीएमसी का 'सुविधा शिविर'

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। एनडीएमसी का मासिक 'सुविधा शिविर' 1 अगस्त (शनिवार) को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर, जय सिंह रोड में आयोजित होगा। शिविर में नए बिजली कनेक्शन, लोड बढ़ाने-घटाने, संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जलभराव, सड़क रखरखाव, पेंशन, बारात घर व पार्क बुकिंग समेत विभिन्न नागरिक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।

आईजीआई हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से करीब नौ किलोग्राम विशिष्ट गांजा जब्त

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से आए एक यात्री को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उसके पास से करीब नौ किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (विशिष्ट गांजा) जब्त किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

हाइड्रोपोनिक वीड गांजे की एक ऐसी किस्म है, जिसे मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से युक्त पानी में उगाया जाता है। इसमें नशीले रसायन की मात्रा अधिक होती है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह यात्री बुधवार को बैंकॉक से यहां पहुंचा था। उसे आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) प्रोफाइलिंग के आधार पर सीमा शुल्क के ग्रीन चैनल से निकलने के बाद रोका गया।

बयान में कहा गया कि यात्री के सामान की एक्स-रे जांच के दौरान अधिकारियों को कुछ संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दीं। बयान में बताया गया कि सामान की गहन जांच किए जाने पर उसमें हवा रहित पांच पैकेट बरामद हुए। इनमें हरे रंग का पदार्थ था, जिसके विशिष्ट गांजा होने की आशंका है। इसका कुल वजन 8,961 ग्राम है।

उपराज्यपाल ने आईकेईए के स्टोर का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को साकेत में आईकेईए के नए स्टोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारत में स्वीडन के राजदूत जान थेस्लेफ और आईकेईए इंडिया के सीईओ पैट्रिक एंटोनी भी मौजूद रहे।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली के बढ़ते परिवारों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए आसान, किफायती और टिकाऊ जीवन-शैली के समाधान बहुत जरूरी हैं। स्वीडन के इस प्रमुख ब्रांड का आना दिल्ली की आर्थिक क्षमता में बढ़ते वैश्विक भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह विकसित दिल्ली के विजन के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय निवेश और व्यापार के लिए दिल्ली को एक पसंदीदा जगह के तौर पर और मजबूत बनाता है।

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन दुनिया उम्मीद और उत्साह के साथ भारत में निवेश कर रही है। इसकी वजह है भारत की विकास गाथा, स्थिर नीतिगत माहौल और इसके विशाल उपभोक्ता बाजार की मजबूती पर भरोसा।

दिल्ली भाजपा का आप कार्यालय पर प्रदर्शन, पेपर लीक पर दोहरे मापदंड का आरोप

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में कैनिंग लेन स्थित आम आदमी पार्टी (आप) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकताओं ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की बर्खास्तगी की मांग की। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने पहुंचाया, जहां करीब एक घंटे बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

प्रदर्शन में सांसद योगेन्द्र चांदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, योगिता सिंह, मोहनलाल गिहारा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर केंद्र और पंजाब में अलग-अलग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में पेपर लीक के मुद्दे पर नैतिकता की बात करने वाली आप पंजाब में हुए कथित पेपर लीक मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि पंजाब में टीईटी, 12वीं अंग्रेजी, फामेर्सी ऑफिसर और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार

जवाबदेही तय नहीं कर रही।

मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र में इस्तीफा, पंजाब में संरक्षण यही है आप का दोहरा चरित्र। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा क्रांति के बजाय पेपर लीक क्रांति बना दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मांग की है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और छात्रों से माफी मांगी जाए।

प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल ने कहा कि पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर पहले चुप्पी और फिर इनकार करने की कोशिश से युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया उजागर हुआ है। सांसद योगेन्द्र चांदोलिया ने कहा कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा से विपक्ष बचता रहा, जबकि पंजाब के मामलों पर भी आप नेतृत्व ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

सांसद कमलजीत सहरावत ने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में पंजाब में कई पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी गलती स्वीकार किए बिना सुधार संभव नहीं है। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि फामेर्सी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में भी आम आदमी पार्टी की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एंटी-पेपर लीक कानून का विपक्ष ने विरोध किया, जबकि पंजाब के मामलों में जवाबदेही से बचा जा रहा है।

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। भाजपा ने आप को चेतावनी दी कि जब तक पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा।

संक्षिप्त वार्ता

सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

कानपुर, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। सावन माह के पहले दिन गुरुवार को शहर के प्रमुख शिवालयों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के से ही परमट स्थित श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर, जाजमऊ के सिद्धनाथ महादेव मंदिर,

नवाबगंज के जागेश्वर महादेव मंदिर, शिवराजपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर, बिठूर के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर और शिवाला स्थित प्रयाग नारायण शिवालय में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। परमट स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। मंगला आरती के बाद शुरू हुआ जलाभिषेक और दर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं सिद्धनाथ, जागेश्वर, खेरेश्वर, वनखंडेश्वर और प्रयाग नारायण शिवालय में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिरों में रुद्राभिषेक, शिव चालीसा पाठ और भजन-कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।

कानपुर में सिद्धनाथ घाट पर गंगा में मिला अज्ञात युवक का शव,पुलिस कर रही जांच

कानपुर, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ घाट के पास गुरुवार को गंगा नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार सुबह घाट पर मौजूद लोगों ने गंगा में एक शव उतराता देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है। फोटो और अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए भी उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि मामला दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से जुड़ा है। घटनास्थल के आसपास से भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

स्वास्थ्य योजनाओं में लापरवाही पर सीडीओ का सख्त एक्शन

दो दिन की डेडलाइन; नहीं सुधरे तो होगी कार्रवाई

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शासन की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान ने जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। योजनाओं की खराब प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में लंबित भुगतान मिलने पर सीडीओ ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले दो दिनों के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा के बाद भी भुगतान लंबित रहने पर संबंधित जिला लेखा प्रबंधक के खिलाफ सेवा से हटाने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा में मड़ावरा विकासखंड की स्थिति सबसे खराब पाई गई, जहां योजना के तहत केवल 32 प्रतिशत भुगतान हुआ था। इस पर सीडीओ ने संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए उसी दिन जिला मुख्यालय पर रहकर सभी लंबित मामलों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए।

नियमित टीकाकरण अभियान की धीमी प्रगति पर भी उन्होंने असंतोष जताया और कहा कि जनपद का कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जखौरा और बिरधा विकासखंड का लगातार खराब प्रदर्शन भी चर्चा का विषय रहा। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दोनों प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. इम्तियाज अहमद, सीएमएस डॉ. गजेन्द्र सिंह, जिला सूचना अधिकारी डी. एस. दयाल, डीपीएम डॉ. रजिया फिरोज, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. सौरभ सक्सेना सहित सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

खेत में मिला 22 वर्षीय युवती का शव, पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

औरैया, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र के पुरवा भूपत गांव में गुरुवार सुबह खेत में 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मृतका की पहचान अंजली उर्फ बबली (22) पुत्री अरविंद कुमार निवासी पुरवा भूपत के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंजली मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसके तीन भाई हैं। वह बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

मीरजापुर में बेकाबू सीमेंट कंटेनर घर में घुसा

मीरजापुर, (वेब वार्ता)। उत्तरप्रदेश के जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत कलना गहरवार गांव में गुरुवार भोर एक भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। प्रयागराज की ओर से आ रहा सीमेंट से लदा कंटेनर (एमपी 19 जेडक्यू 9901) अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गया और पलट गया।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, कानपुर नगर का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ सम्पन्न

वेब वार्ता, कानपुर

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, कानपुर नगर की नवगठित कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को गैंजेस क्लब, कानपुर में गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, निदेशक उर्सला चिकित्सालय, अपर निदेशक कानपुर मंडल, सीएमएस कांशीराम ट्रॉमा सेंटर, उर्सला चिकित्सालय, डफरिन चिकित्सालय, केपीएम चिकित्सालय तथा कानपुर जनपद के वरिष्ठ चिकित्सकों ने सहभागिता की।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, कानपुर नगर के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित डा. अमित सिंह गौर तथा सचिव पद पर डा. संगम सिंह सचान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसके अलावा उपाध्यक्ष (महिला) पद पर डा. दीपमाला चक, उपाध्यक्ष (सामान्य) के दो पदों पर डा. अनुज दीक्षित एवं डा. नीरज सचान, वित्त सचिव पद पर उर्सला चिकित्सालय के डा. मुन्नालाल विश्वकर्मा, सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी पद पर डेंटल सर्जन डा. शेख हसनैन तथा संपादक पद पर डा. शशि रंजन पटेल ने भी शपथ ग्रहण की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. अमित सिंह गौर वर्तमान में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा पूर्व में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डा. यशवीर सिंह रहे। इस अवसर पर महासचिव डा. शरद वैश्य, उपाध्यक्ष डा. जगमोहन, उपाध्यक्ष डा. यशोवर्धन सिंह, उपाध्यक्ष (मुख्यालय) डा. मोहित सिंह, वित्त सचिव डा. प्रवीण कुमार, संगठन मंत्री डा. धीरज मिश्रा तथा संपादक डा. मो. जमील अनवर सहित प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की सम्पूर्ण केन्द्रीय टीम उपस्थित रही।

बकाया मानदेय को लेकर शिक्षा प्रेरकों का आक्रोश, गांधी भवन में चिंतन बैठक

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 30 जुलाई। साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कार्य कर चुके शिक्षा प्रेरकों ने अपने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को गांधी भवन में चिंतन-मंथन बैठक आयोजित की। बैठक में प्रेरकों ने वर्षों से लंबित भुगतान पर नाराजगी जताते हुए शासन और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि साक्षर भारत मिशन के दौरान उन्होंने पल्स पोलियो अभियान, जनधन खातों के सत्यापन, राशन कार्ड सत्यापन समेत शासन द्वारा सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। उनका कहना था कि मिशन समाप्त होने के बाद 31 मार्च 2018 तक सभी आवश्यक अभिलेख और सत्यापन रिपोर्ट संबंधित कार्यालयों में जमा करा दी गई थीं। इसके बावजूद भुगतान प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। प्रेरकों के अनुसार, मिशन समाप्त होने के समय जनपद में 2202 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1850 शिक्षा प्रेरक कार्यरत थे, जबकि करीब 352 पद रिक्त थे। उनका आरोप है कि वर्तमान में भुगतान में देरी के लिए कागजी सत्यापन और बैंक खातों के अपडेट में विसंगतियों का हवाला दिया जा रहा है, जिससे हजारों परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बैठक में प्रेरकों ने कहा कि यदि ब्याज सहित भुगतान संभव नहीं है, तो कम से कम 10 माह का मूल बकाया (एरियर) उनके खातों में जारी किया जाए। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के बीच लंबे समय से लंबित भुगतान के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। प्रेरकों ने प्रशासन से लंबित प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश होंगे।

संडीला में सड़क किनारे मिले दो युवकों के शव, हत्या की आशंका

आईजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, खुलासे को तीन टीमें गठित

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। संडीला कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह सड़क किनारे दो युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानकर जांच में जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। फोरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 9:37 बजे डायल-112 पर सूचना मिली कि अतरौली मार्ग पर तकिया-आटामऊ जाने वाली सड़क पर निमार्णाधीन जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से करीब 500 मीटर पहले सड़क किनारे दो युवकों के शव पड़े हैं। सूचना मिलते ही संडीला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी।

मृतकों की पहचान अरुण चौरसिया (26) पुत्र जयप्रकाश चौरसिया निवासी ग्राम रेसों, थाना कछौना तथा अभिषेक चौरसिया (27) पुत्र शिवराम चौरसिया निवासी ग्राम गौहनिया, थाना कछौना के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। दोनों युवकों के शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

दोनों युवकों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात कहीं और अंजाम देकर शव यहां फेंके गए या घटना इसी स्थान पर हुई। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं।

घटना की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से अब तक की जांच की जानकारी ली और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना करने के निर्देश दिए। साथ ही घटना के शीघ्र अनावरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। घटनास्थल एवं आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

घटना के खुलासे के लिए क्षेत्राधिकारी संडीला एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम एवं फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद घटना के कारणों और हत्या के तरीके को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क किनारे दो युवकों के शव मिलने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए हैं। तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर और उठती लहरों को देखते हुए नाव संचालन पर लगी रोक

वाराणसी, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में जिला प्रशासन में गुरुवार को गंगा नदी में चलने वाली सभी नावों पर रोक लगा दी। जल पुलिस द्वारा जिला प्रशासन के आदेश को नाविकों को बताया गया। पुलिस कर्मियों ने कहा कि हवाएं तेज चल रही हैं, गंगा नदी में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस कारण अगले आदेश तक नाव के संचालन पर रोक लग गई है। जल पुलिस के कर्मचारियों ने विभागीय नाव पर सवार होकर माइक लेकर घाटों के किनारे जोर-जोर से अपील करते हुए उक्त जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि घाटों पर नहा रहे श्रद्धालुओं को विशेष सतर्कता बरतनी है। नदी में उठ रही लहरों के कारण कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है।

कुपोषण मुक्त हरदोई पर डीएम का जोर

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में गुरुवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुपोषण की रोकथाम, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं और विभिन्न पोषण योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक डाटा समयबद्ध रूप से

संकलित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने संडीला एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) से संबद्ध सभी विकास खंडों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को निर्देशित किया कि क्षेत्र के चिन्हित कुपोषित बच्चों को एनआरसी भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही उनके अभिभावकों की समुचित काउंसिलिंग कर एनआरसी में मिलने वाली सुविधाओं और उपचार की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

बॉडी वोन कैमरे से लैश होंगे टीटी

ट्रेन में चेकिंग के दौरान यात्रियों और टीटी के बीच रहेगी पारदर्शिता

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

कानपुर। अब टीटी और यात्रियों के बीच होने वाले विवाद को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिये रेलवे ने एक पहल करते हुये टीटी को " बॉडी वोन कैमरेस से लैश किया है। इससे चेकिंग के दौरान कोई भी वाद विवाद टीटी और यात्रियों के बीच होने पर कैमरे में कैद हो सकेगा और उसी साक्ष्य के आधार पर करवाई हो सकेगी।

आमतौर पर देखा जाता है की ट्रेन में सफर के दौरान टिकट चेकिंग के दौरान टीटी और यात्रियो में विवाद हो जाता है और वसूली, या सीट के नाम पर अधिक पैसे मांगने का आरोप टीटी पर लगता है। साक्ष्य न होने पर कई बार गलत करवाई हो जाती है.. इसी वजह से रेलवे ने टीटी को बॉडी वोन कैमरे से लैश किया है। यह सबसे पहले प्रयागराज एक्सप्रेस और श्रमशक्ति एक्सप्रेस से की जा रही है। 6-6 टीटी की टीम बनाई गई जोकि ट्रेनों में चेकिंग के दौरान बॉडी वोन कैमरा लगायें रहैंगे, जिससे की हर तरह की गतिविधि कैमरे में कैद हीं सकेगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। करवाई में कैमरे में होने वाली रिकॉडिंग साक्ष्य का काम करेंगी। हालांकि रेलवे की यह व्यवस्था कितनी कारगर साबित होगी यह तो समय बताएगा, लेकिन 2 ट्रेनों में ट्रायल शुरू किया गया है और टीटी ने कैमरे के साथ अब चेकिंग शुरू कर दी है और वसूली के आरोप से कितना बचेंगे यह देखने वाली बात होंगी। डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने बताया की 2 ट्रेनों में व्यवस्था शुरू की गई और जल्द और ट्रेनों में भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।

कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर हुआ मंथन

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने की। इसमें यात्रा मार्गों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तण्ड प्रकाश ने कांवड़ यात्रा में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को

निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जाए और संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारु रहे, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ ड्यूटी करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ड्यूटी के दौरान अनुशासन, संयम और संवेदनशीलता बनाए रखें तथा श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी हरियावां, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर, क्षेत्राधिकारी यातायात सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम

कृषि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज से शिक्षा-स्वास्थ्य में बड़ा सुधार

कुशीनगर। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और शांति व करुणा के वैश्विक संदेश की पावन भूमि कुशीनगर आज उत्तर प्रदेश के विकास मानचित्र पर एक नई पहचान गढ़ रही है।

अस्सी वर्ष की अवस्था में जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, वह पावन धरा आज केवल आध्यात्मिक शांति की तलाश में आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं का केंद्र ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय और उद्योग आधारित विकास का एक सशक्त मॉडल बनकर उभर रही है।

वैश्विक धार्मिक पर्यटन और सर्वकालिक हवाई कनेक्टिविटी

कुशीनगर पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ जापान, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, ताइवान, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों से हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु नमन करने पहुँचते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर, रामभार स्तूप और फाजिलनगर जैसी धरोहरों के बीच पर्यटकों की सुगमता के लिए लगभग 377 करोड़ रुपये की लागत से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। हाल ही में इस हवाई अड्डे को कैट-आइज और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (कछर) जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है, जिससे अब दिन-रात और किसी भी मौसम में यहाँ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और विमान सुरक्षित लैंड कर सकते हैं।

कृषि प्रधान जिला होने के नाते कुशीनगर में धान, गेहूं और गन्ने के साथ-साथ लगभग 21 हजार हेक्टेयर में केले की व्यापक खेती होती है। 'एक जिला एक उत्पाद' (डउढढ) योजना के तहत केले के बेकार समझे जाने वाले तनों से रेशा निकालकर हैंडबैग, योगा मैट, रस्सियां, गमले और पेन स्टैंड जैसे हस्तशिल्प उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हरिहरपुर जैसे गांवों में स्थानीय उद्यमियों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिससे कभी खेत का कचरा माना जाने वाला तना अब हजारों परिवारों की आजीविका और समृद्धि का जरिया बन चुका है।

अब बड़े शहरों की निर्भरता समाप्त हो गई है

कभी इंसेफेलाइटिस और कालाजार जैसी गंभीर बीमारियों के दंश के लिए जाने जाने वाले इस पूर्वांचल क्षेत्र में अब स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी संरचना पूरी तरह बदल चुकी है। करीब 750 करोड़ रुपये की लागत से महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर और बलिया सहित पूर्वांचल के 10 जिलों के युवाओं और शोधार्थियों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। इसके साथ ही, जिला अस्पताल से संबद्ध राजकीय मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू हो चुका है, जहाँ अत्याधुनिक ट्रॉमा व क्रिटिकल केयर सेंटर, डायलिसिस यूनिट और नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था की गई है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब बड़े शहरों की निर्भरता समाप्त हो गई है।

केले के रेशे से उत्पाद, महिला सशक्तिकरण और आजीविका का नया स्रोत

...संभावनाओं को पंख दिये हैं

पूर्व की 'गन्ना, गंडक और गुंडा' वाली पहचान को पीछे छोड़ते हुए कुशीनगर में अब फोरलेन सड़कों, स्टेट हाईवे और कप्तानगंज जैसे स्टेशनों से वंदे भारत रेल कनेक्टिविटी के जरिए व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिली है। इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 1300 करोड़ रुपये के एमओयू (टडव) और बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों ने यहाँ औद्योगिक संभावनाओं को पंख दिए हैं। इसके साथ ही, जिले की 72 मॉडल ग्राम पंचायतों द्वारा खुद की आय अर्जित करने के अभिनव प्रयासों से गाँव-देहात की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, जिससे कुशीनगर 'बढ़ते उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है।

यूक्रेन ने कहा- भारत बात नहीं कर रहा, हालात बिगड़ रहे

नई दिल्ली। यूक्रेन ने ब्लैक सी (काला सागर) में सुरक्षा हालात को लेकर भारत की हालिया समुद्री एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं। यूक्रेन का कहना है कि क्षेत्र में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के बावजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब यूक्रेन के चोनोमोर्स्क बंदरगाह पर एमवी एएमआईआर1 जहाज में 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं।

नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने नौवहन महानिदेशालय की ओर से जारी दो अलग-अलग सुरक्षा एडवाइजरी की तुलना करते हुए सवाल उठाए हैं। यूक्रेन के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए जारी एडवाइजरी में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और शिपिंग कंपनियों को अगले आदेश तक उस क्षेत्र में भारतीय चालक दल भेजने से बचने की सलाह दी गई थी। वहीं, ब्लैक सी के लिए जारी एडवाइजरी में ऐसी सख्ती नहीं दिखाई गई। यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि ब्लैक सी में लगातार हमलों के बावजूद सुरक्षा उपायों का स्तर वहां मौजूद खतरे के अनुरूप होना चाहिए। यूक्रेन का दावा है कि नागरिक जहाजों पर हो रहे हमलों में भारतीय नाविक भी प्रभावित हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त

सावधानी की जरूरत है। यूक्रेन के अनुसार, विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस मुद्दे पर बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यूक्रेन का कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बढ़ाना चाहता है।

एमवी एएमआईआर1 जहाज पर फंसे 13 भारतीय नाविकों को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें हरसंभव सहायता दी जा रही है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास भी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय दूतावास ने पहले ही कहा था कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास कर रहा है। यूक्रेन ने भारतीय नाविक संघ की उस मांग का भी समर्थन किया है, जिसमें उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। यूक्रेनी दूतावास ने उम्मीद जताई है कि भारत का विदेश मंत्रालय और नौवहन महानिदेशालय ब्लैक सी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यह मामला समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रहा है।

महत्वपूर्ण ख़बर

साल 2050 तक समुद्र में समा जाएंगे कई तटीय शहरः नासा

- वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से तबाही मचा रहा है और 2050 तक दुनिया के कई तटीय शहर समुद्र में समा सकते हैं। अगले 26 सालों में समुद्र का स्तर कम से कम 1 फुट (लगभग 30 सेंटीमीटर) तक बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में तो यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा भयानक होगी, जिससे तूफान, बाढ़ और हाई टाइड्स का भयानक जंजाल उठेगा और कई शहरों के नामोनिशान मिटने का खतरा मंडरा रहा है।

नासा के दशकों पुराने सैटेलाइट डेटा और तटीय गेज रिकॉर्ड्स के विश्लेषण से पता चला है कि गल्फ कोस्ट पर इसका सबसे ज्यादा असर होने वाला है, जहां समुद्र का स्तर 14 से 18 इंच तक बढ़ सकता है। न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन, टाम्पा और मोबाइल जैसे शहर पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं, और महज 24 साल बाद इनकी सड़कें, घर और बंदरगाह हमेशा पानी में ही डूबे नजर आएंगे।

हथौड़ा नहीं वो जिंदा हैंड ग्रेनेड निकला, खुलासे से मची सनसनी

- बीजिंग। चीन में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला करीब 20 वर्षों तक जिस भारी धातु की वस्तु को सामान्य हथौड़ा समझकर घरेलू कामों में इस्तेमाल करती रहीं, वह वास्तव में चीन की सेना का सक्रिय टाइप-67 हैंड ग्रेनेड निकला। लंबे समय तक इस्तेमाल के बावजूद ग्रेनेड का विस्फोट नहीं होना विशेषज्ञों के लिए भी हैरानी का विषय बना हुआ है।

यह मामला चीन के हुबेई प्रांत के हुआंगबाओ काउंटी का है। जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला को करीब दो दशक पहले खेत में काम करने के दौरान यह धातु की वस्तु मिली थी।

दीपके ने कहा- जरुरत पड़ी तो कल ही बदल देंगे सरकार

छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं होने भड़की सीजेपी

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गईं तो उनका संगठन नए सिरे से बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को परेशान करना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। दीपके ने यह भी कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं, उन्हें अपराधियों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोग अपनी पर आ गए तो कल ही सरकार बदल देंगे।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से लोगों का आक्रोश खत्म हो गया है, तो यह उसकी गलतफहमी है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों और युवाओं में अब भी व्यापक नाराजगी है और यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो अगला आंदोलन पहले से कहीं बड़ा होगा। एक सवाल के जवाब

में दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने की बात भी कही। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सार्वजनिक जीवन में दूसरी भूमिका अपनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं करेगी तो युवा लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाने का प्रयास करेंगे।

दीपके ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली में लगभग एक महीने तक आंदोलन का नेतृत्व किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि करीब 40 दिन बाद अपने घर लौटने पर उन्हें सबसे अधिक खुशी अपने माता-पिता से मिलने की है। उनके अनुसार, भारत आने के बाद से वह लगातार आंदोलन में व्यस्त रहे और लगभग 36 दिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिताए। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन समाप्त होने के बाद भी कई राज्यों में छात्रों को परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस छात्रों के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है। दीपके ने आरोप लगाया कि संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ बल प्रयोग हुआ और अब भी उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने सरकार से इस तरह की कार्रवाई रोकने की मांग की।

लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने कहा कि केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार, जब तक व्यवस्था और जिम्मेदार लोगों की नीयत में बदलाव नहीं आएगा, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट-ट्रैक कोर्ट में पहली ही सुनवाई स्थगित हो गई, जिससे न्याय प्रक्रिया की गति पर भी सवाल खड़े होते हैं।

चीन ने 21 मीटर लंबा 582 टन वजन वाला बना डाला खुद का सूरज

बीजिंग। दुनियाभर में ऊर्जा के बढ़ते संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच चीन ने ऊर्जा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। चीन ने सूर्य की कार्यप्रणाली पर आधारित कार्बन-फ्री ऊर्जा उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 582 टन वजनी सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का सफल परीक्षण किया है। नाभिकीय संलयन (न्यूक्लियर फ्यूजन) पर आधारित इस तकनीक को कृत्रिम सूरज कहा जा रहा है, क्योंकि यह उसी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करेगा जिससे सूर्य पर असीमित ऊर्जा बनती है।

चीन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस तकनीक के जरिए व्यावसायिक रूप से बिजली उत्पादन शुरू करने का है। इस विशालकाय डी-शेप टोरोयडल फील्ड सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई लगभग उतनी ही विशाल है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का संलयन 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक उच्च तापमान पर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि बिना किसी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के स्वच्छ और असीमित ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी।

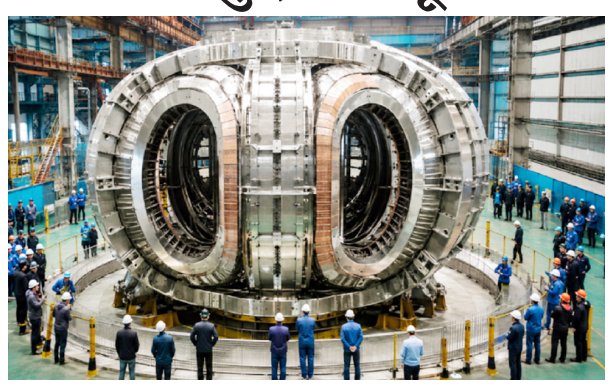

विशेषज्ञों के अनुसार, यह अब तक का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर मैग्नेट है। इसका मुख्य कार्य 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म की गई प्लाज्मा गैस को नियंत्रित और कैद करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र (मैग्नेटिक फील्ड) पैदा करना है। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यह बेहद गर्म गैस रिएक्टर की अंदरूनी दीवारों को नहीं छू पाएगी। ठीक वैसे ही जैसे किसी कार में स्पार्क प्लग काम करता है, इसमें लगा सुपरकंडक्टिंग सेंट्रल सोलिनॉइड कॉइल गैस को अत्यधिक गर्म करने का काम करेगा। परीक्षण के दौरान इस मैग्नेट ने 60 किलोएम्पीयर करंट और 6.03 मेगाजूल ऊर्जा को संभालने की अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। इसे विकसित करने वाली वैज्ञानिक टीम ने 6 वर्षों के इस गहन अभियान के दौरान 47 नए पेटेंट दर्ज कराए हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह उपकरण लगभग 60 वर्षों तक सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। यदि चीन का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल रहता है, तो भविष्य में बड़े उद्योगों और शहरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकेगा। यह तकनीक भविष्य में दुनिया को हरित और टिकाऊ ऊर्जा देने में गेमचेंजर साबित होगी।

सख्त सजा से ज्यादा जरुरी है पेपर लीक होने की संभावना को खत्म करना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर सख्ती बढ़ाने के उद्देश्य से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को बुधवार को लोकसभा से ध्वनिमत से पारित करा लिया। विधेयक में पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों के लिए कड़ी सजा, भारी जुमार्ने, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया गया है। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने इस कानून को अधूरा बताते हुए कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के मूल उपायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार का ध्यान मुख्य रूप से पेपर लीक होने के बाद की कार्रवाई पर है, जबकि सबसे जरूरी सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं को होने से पहले कैसे रोका जाए। उनके अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त सजा और भारी जुमार्ना आवश्यक हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों को दूर किए बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। रांका ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में व्यापक सुधार किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को वैधानिक निकाय का दर्जा मिले, परीक्षा कैलेंडर और पाठ्यक्रम में पारदर्शिता लाई जाए तथा परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े वेंडरों और कोचिंग संस्थानों की सख्त निगरानी हो। उन्होंने कहा कि ब्लैकलिस्ट किए गए वेंडरों को दोबारा काम करने

से रोकना, डिजिटल और भौतिक ऑडिट को अनिवार्य बनाना तथा पूरी परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना समय की मांग है।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। उनका कहना है कि यह केवल कानून का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है।

लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा भी हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। संशोधित कानून के तहत प्रश्नपत्र लीक करने या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करने पर न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की सजा तथा 50 लाख रुपये तक जुमार्ने का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम सात वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपये तक जुमार्ना लगाया जा सकेगा। साथ ही सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के अंदर मुकदमे का निपटारा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस बीच केंद्र सरकार पहले ही परीक्षा सुधारों के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर चुकी है।

यह समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक सुझाव तैयार करेगी।

अब ब्रिटेन तक अडानी का साम्राज्य? 21 पोर्ट खरीदने की तैयारी!

नई दिल्ली। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ब्रिटेन के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स (एबीपी) में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। यदि यह रणनीतिक सौदा सफल होता है, तो अडानी समूह का साम्राज्य भारत से लेकर ब्रिटेन तक फैल जाएगा। यह कदम अडानी ग्रुप की वैश्विक बंदरगाहों में उपस्थिति को और अधिक मजबूत करेगा और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनने के उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को एक बड़ी गति प्रदान करेगा।

जानकारी के अनुसार, एबीपी की लगभग 63.9 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी बिक्री के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में यह हिस्सेदारी कनाडा के दो प्रमुख पेंशन फंड- कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) और आंटारियो म्युनिसिपल इम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम के पास है। दोनों निवेशकों ने अपनी-अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंकरों की नियुक्ति कर दी है। एबीपी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में कुल 21 बंदरगाहों का संचालन करता है। इनमें ब्रिटेन का सबसे बड़ा बंदरगाह इमिंघम और प्रमुख आयात बंदरगाह साउथेम्पटन शामिल हैं। यह कंपनी ब्रिटेन के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा संभालती है। वर्ष 2025 में एबीपी ने 42.5 मिलियन टन बल्क कार्गो तथा 3.1 मिलियन कंटेनर और रोल-ऑन/रोल-ऑफ यूनिट्स का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इस दौरान कंपनी का राजस्व 819.8 मिलियन पाउंड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 586.5 मिलियन पाउंड दर्ज किया गया था। लोंगटर्म अनुबंधों से मिलने वाली स्थिर आय के कारण यह संपत्ति अडानी पोर्ट्स के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्तमान में अडानी पोर्ट्स भारत में 15 बंदरगाहों का संचालन कर रही है, जिनकी कुल क्षमता 653 मिलियन टन है। इसके अतिरिक्त कंपनी की उपस्थिति इजरायल, तंजानिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 501 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया।

आगरा किले में निखरेगी जहांआरा और रोशनआरा महल की ऐतिहासिक चमक

आगरा। विश्व धरोहर आगरा किले में स्थित मुगलकालीन जहांआरा और रोशनआरा महल की ऐतिहासिक सुंदरता को फिर से संवारने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। एएसआई की रसायन शाखा दोनों स्मारकों पर मडपैक ट्रीटमेंट (मुल्तानी मिट्टी का लेप) कर रही है, जिससे संगमरमर पर जमी धूल, प्रदूषण और पर्यटकों के लगातार स्पर्श से पड़े पीलेपन को हटाया जाएगा। करीब 12 लाख रुपये की लागत वाली यह परियोजना सितंबर के मध्य तक पूरी होने की संभावना है।

यहां बताते चलें कि आगरा किले के अंगूरी बाग परिसर में स्थित खास महल के उत्तर में जहांआरा और दक्षिण में रोशनआरा की छतरियां बनी हुई हैं। इनका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पुत्रियों के लिए कराया था। दोनों स्मारकों के बाहरी हिस्से में सफेद संगमरमर और भीतरी भाग में चूने का सफेद प्लास्टर है, जबकि छत पर तांबे की प्लेटें लगी हुई हैं। समय के साथ धूल, नमी और पर्यटकों के स्पर्श के कारण इनकी चमक फीकी पड़ गई है। एएसआई के संरक्षण कार्य के तहत संगमरमर और प्लास्टर की सतह पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जा रहा है। सूखने के बाद इस लेप को पानी से साफ किया जाएगा, जिससे सतह पर जमी गंदगी और धूल हट जाएगी तथा मूल चमक वापस लौट आएगी। इसके साथ ही छत पर लगी तांबे की प्लेटों की विशेष सफाई और रासायनिक संरक्षण भी किया जाएगा, जिससे वे फिर से सुनहरी आभा के साथ दमकने लगेंगी। इतिहास के अनुसार, जहांआरा और रोशनआरा मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थीं। जहांआरा ने दारा शिकोह का साथ दिया था, जबकि उत्तराधिकार के युद्ध में रोशनआरा ने औरंगजेब का समर्थन किया। जहांआरा को आगरा की जामा मस्जिद के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है।

लंबे समय से समुद्र में ठहरे जहाजों पर पनप रहे समुद्री जीव

तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब लगभग पाँच महीनों से फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बनाए हुए है। इस संघर्ष के कारण लगभग पंद्रह सौ जहाज फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं, जबकि कई सौ अन्य जहाज पास की ओमान की खाड़ी में फंसे हैं। लंबे समय से समुद्र में ठहरे इन जहाजों पर अब समुद्री जीव पनप रहे हैं, और आशंका है कि जंग के रुकने के बाद आवाजाही शुरू होने पर ये जीव दुनिया के कोने-कोने में पहुँच जाएँगे, जिससे एक बड़ा पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकता है। एक नई स्टडी के अनुसार, व्यापार फिर से शुरू होने पर इन जहाजों पर पनप रहे जीव दुनिया भर में फैल सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल साइंस और वुड्स होले ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन सहित चौबीस समुद्री वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा तैयार की गई इस स्टडी के

अनुसार, लंबे समय तक एक ही जगह लंगर डाले रहने के कारण जहाजों के निचले हिस्से पर एल्गी, बार्नकल, मसेल और बिना रीढ़ वाले इनवर्टिब्रेट जीव समुदाय जमा हो जाते हैं, जिसे बायोफाउलिंग कहते हैं। व्यापार के शुरू होते ही ये जीव पूरी दुनिया में पहुँच सकते हैं। शोधकताओं ने पंद्रह सौ से अधिक जहाजों के इस ठहराव को वैश्विक समुद्री आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की एक संभावित सुपर-स्प्रेडर स्थिति करार दिया है।

वुड्स होले ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन में जीवविज्ञानी कैरोलिन टेपोल्ट ने बताया कि समुद्री आक्रामक प्रजातियाँ दुनिया भर के तटों पर गंभीर पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभाव डालती हैं। एक बार जब ये किसी नए जगह पर जम जाती हैं, तो इन्हें खत्म करना लगभग असंभव हो जाता है। ग्लोबल शिपिंग में आई इस रुकावट ने ना केवल व्यापार को प्रभावित किया है, बल्कि चुपके से गर्म पानी की प्रजातियों को नए बंदरगाहों तक फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी बना दी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की सलाह है कि तीस दिनों से अधिक समय तक निष्क्रिय खड़े जहाजों को यात्रा शुरू करने से पहले बायोफाउलिंग मैनेजमेंट की तत्काल जरूरत होती है। हालांकि, ये जहाज समुद्री जीवों की वृद्धि और प्रजनन के मुख्य मौसम में लगभग चार महीनों से अटके हुए हैं।

ऊंचाई के हिसाब से बदल जाता है जंगलों के कार्बन भंडारण का तरीका

नई दिल्ली। पहाड़ों पर ऊंचाई के हिसाब से जंगलों के कार्बन भंडारण का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। यह दावा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अरविंद सिंह और विनोद प्रसाद खंडूरी ने अपनी टीम के साथ गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में किए गए एक व्यापक अध्ययन किया है। भारतीय हिमालय के जंगल जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में कार्बन को संग्रहित करते हैं। यह खोज दिखाती है कि ज्यादा ऊंचाई पर स्थित देवदार के विशाल जंगल अपनी लकड़ियों में भारी मात्रा में कार्बन छिपाते हैं, जबकि कम ऊंचाई वाले मिश्रित (मिक्स्ड) जंगल मुख्य रूप से मिट्टी के अंदर कार्बन को सुरक्षित रखते हैं। यह नई जानकारी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई को पूरी तरह से बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने अपनी इस पड़ताल के लिए गढ़वाल हिमालय में तीन अलग-अलग ऊंचाई पर स्थित जंगलों को चुना। सबसे अधिक ऊंचाई (1900 से 2300 मीटर) पर देवदार के जंगल पाए गए, जहां सेड्रस देवदारा जैसे विशाल और सदियों पुराने पेड़ मौजूद हैं। इन देवदार के पेड़ों को सबसे बड़े कार्बन बैंक के रूप में पाया गया, जो अकेले बायोमास में प्रति हेक्टेयर 230.85 से 274.85 मेगाग्राम कार्बन

स्टोर करते हैं। यह आंकड़ा सभी प्रकार के जंगलों में सर्वाधिक था, जो इन पेड़ों की दशकों पुरानी लकड़ियों में कार्बन जमा होने का प्रमाण है।

ये पेड़ सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं और हर साल इनके तने और शाखाएं मोटी होती जाती हैं। बीच की ऊंचाई (1550 से 1950 मीटर) पर चीड़ के जंगल (पिनस रॉक्सबर्घी प्रजाति) भी कार्बन जमा करते हैं, लेकिन देवदार की तुलना में कम मात्रा में। इसके विपरीत, सबसे कम ऊंचाई (500 से 1000 मीटर) पर मौजूद चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित जंगल जमीन के अंदर कमाल कर रहे थे। इन जंगलों की मिट्टी में सबसे ज्यादा लेबाइल कार्बन (7.43 मिलीग्राम प्रति ग्राम) और नॉन-लेबाइल कार्बन (2.06 मिलीग्राम प्रति ग्राम) पाया गया। साथ ही, यहां सबसे बड़ा सक्रिय कार्बन पूल (13.48 टन प्रति हेक्टेयर) और निष्क्रिय कार्बन पूल (6.41 टन प्रति हेक्टेयर) भी दर्ज किया गया। इन जंगलों की खूबी यह है कि वे गिरे हुए पत्तों और सड़ी हुई जड़ों को तेजी से कार्बन में बदलकर मिट्टी में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, जिससे यह कार्बन वायुमंडल में वापस जाने से रुक जाता है। यह अंतर दशार्ता है कि जंगल की जमीन पर जो भी सड़ता है, वह बहुत जल्दी कार्बन बनकर मिट्टी में मिल जाता है। कार्बन भंडारण की इस ऊंचाई-आधारित भिन्नता का सीधा असर वन प्रबंधन नीतियों पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने जोर दिया है कि पहाड़ों पर कार्बन बचाने के लिए कोई एक नियम लागू करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे हम प्रत्येक इकोसिस्टम की विशिष्ट जरूरतों को नजरअंदाज कर देंगे।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 गांवों का होगा चयन

प्रत्येक ग्रामसभा को मिलेगी 15 लाख की स्वीकृति

रायपुर। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 ग्रामों का चयन निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इन ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (सीएफआरएमपी) तैयार कर लागू की जाएगी। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 15 लाख रूपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

आदिम जाति विभाग द्वारा कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्रामसभा में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो ग्रामसभा के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी निभाएगी। इसके लिए ग्रामसभा के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल करंट अकाउंट भी खोला गया है।

पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राज्य सरकार ने जिलों से ऐसे 160 गांवों का चयन क्लस्टर आधारित और परस्पर जुड़े क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

पत्र में कहा गया है कि योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार तकनीकी सहयोगी, सिविल सोसायटी संगठनों तथा स्थानीय संस्थाओं की सेवाएं भी ले सकेगी। इन संस्थाओं की सेवाएं ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं विधिवत अनुमोदन के बाद लिया जा सकेगा। ये संस्थाएं ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन तथा निगरानी में सहयोग देंगी।

आदिम जाति विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि इस पहल से वन अधिकार अधिनियम-2006 का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन होगा, ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत होगी तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और आजीविका संवर्धन को नई गति मिलेगी।

ताजा खबर

संक्षिप्त

रायपुर रेलवे स्टेशन पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य अभियान का आयोजन

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के मंडलीय रेलवे चिकित्सालय द्वारा 28 जुलाई 2026 को रेलवे स्टेशन पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद के मार्गदर्शन पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. के.पी.एस. कासीपथी के निर्देशन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी प्रबंधन एवं जीवनरक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करना था। स्वास्थ्य अभियान में कुल 38 रेलवे कर्मचारियों (23 पुरुष एवं 15 महिला) ने भाग लिया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 06 कर्मचारी उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) तथा 04 कर्मचारी मधुमेह (डायबिटीज) से प्रभावित पाए गए।

विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने युवाओं ने उठाया नशामुक्ति का बीड़ा

रायपुर। विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने तथा युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के उद्देश्य से 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत विजन' एवं नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सूरजपुर जिले में जिला स्तरीय युवा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सूरजपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से लगभग 250 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक सोच, सामाजिक उत्तरदायित्व, आत्मसंयम तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ, भाषण, चित्रकला तथा ऑनलाइन नारा लेखन जैसी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों और इससे दूर रहने के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सामाजिक संवेदनशीलता, जागरूकता और रचनात्मक प्रतिभा विशेष रूप से देखने को मिली। कार्यक्रम में श्री शंभु प्रसाद निषाद, श्री रामचन्द्र सोनी तथा श्री राम कुशल तिवारी निर्णायक मंडल के सदस्य रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को कार्यक्रम के अंत में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया।

नया रायपुर में ललित कला अकादमी कमेटी की मीटिंग हुई

भिलाई। ललित कला अकादमी, रीजनल सेंटर की भिलाई में स्थापना हेतु नवनिर्मित कमेटी का नया रायपुर में मीटिंग संपन्न हुआ। कलाकारों के विशेषज्ञ समिति ने अपने सुझाव संस्कृति विभाग के डायरेक्टर (डॉ. संजय कन्नौजे) आई.ए. एस. को प्रस्तुत किया। इस दौरान कमेटी के चेयरमैन एवं प्रख्यात मूर्तिकार डॉ. अंकुश देवांगन, अंतरराष्ट्रीय चित्रकार हुकुम लाल वर्मा, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर व सुप्रसिद्ध चित्रकार संदीप किन्डो, प्रसिद्ध मूर्तिकार तृप्ति खरे विशेष रूप से मौजूद थे।

राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा और बस्तर में विकसित होंगे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए औद्योगिक पार्क, राज्य सरकार ने दी मंजूरी

उद्योग, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चार नए औद्योगिक पार्क (मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत औद्योगिक विकास योजना की राज्य स्तरीय समीति का बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। समिति की दूसरी बैठक के दौरान प्रदेश के चार जिलों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा का गई और उन्हें स्वीकृति दी गई। राजनांदगांव जिले में स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पटेवा, धमतरी जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, धूम्रपाली, जांजगीर-चांपा जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सलखान और बस्तर जिले में मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नियानार में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। भारत औद्योगिक योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी औद्योगिक विकास नीति के तहत प्रभावी रूप से लागू किया है। राज्य में इस योजना के सुचारू संचालन और विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध मंजूरी देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

मुख्य सचिव ने सिंचाई परियोजनाओं को अधिक व्यवहारिक, टिकाऊ और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर दिया जोर

जशपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की 72वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जशपुर जिले के विकासखंड कुनकुरी अंतर्गत प्रस्तावित योजना के हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन शीर्ष कार्य, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं बहुद्देशीय उद्वहन सिंचाई योजना सहित बेमेतरा जिले की शिवनाथ नदी में ग्राम मोतिमपुर-बिरौदा एनीकट के बैराज में परिवर्तन एवं उद्वहन सिंचाई योजना के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित योजनाओं का पुन: री-मॉडलिंग एवं री-वर्क किया जाए, ताकि परियोजनाएं अधिक व्यवहारिक, टिकाऊ और संसाधनों-संरक्षण आधारित बन सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के निर्माण में जल संरक्षण, बेहतर वर्क मैनशिप और आधुनिक तकनीकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से नहर आधारित प्रणाली के स्थान पर समर्पित पाइपलाइन प्रणाली की व्यवहार्यता का भी गहन अध्ययन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पाइप आधारित प्रणाली अधिक विश्वसनीय, जल की कम हानि वाली, कम लागत एवं समय में पूर्ण होने वाली हो सकती है तथा इससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी काफी कम होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना में ऑप्शन एनालिसिस अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन कर सबसे प्रभावी और किफायती मॉडल का चयन किया जा सके। साथ ही, परियोजनाओं की आगामी 5 से 10 वर्षों की संचालन एवं रखरखाव की रणनीति भी पहले से स्पष्ट रूप से तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि नए प्रस्ताव तैयार करने से पहले वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का पुन: परीक्षण कर आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जिससे जनहितकारी परियोजनाओं का निर्माण सुनिश्चित हो सके।

समय-सीमा बैठक में रायपुर कलेक्टर सख्त

पेंडिंग शिकायतें जल्द निपटाने के निर्देश, योजनाओं के डेवलपमेंट की समीक्षा

रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मंगलवार को रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर अलग-अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा की।

उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, जन शिकायतों और लंबित प्रकरणों के समय पर निराकरण पर जोर देते हुए अधिकारियों को तय समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने पीजी पोर्टल, कलेक्टर कॉल सेंटर, मुख्यमंत्री जनदर्शन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित मामलों की समीक्षा की। प्रोजेक्ट समन्वय के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश

आयुष्मान कार्ड निर्माण और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाता सुधार की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को जल्द लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का कार्य सभी गांवों में समय पर पूरा करने और ड्रोन सर्वे से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

कई अधिकारी रहे मौजूद

कलेक्टर ने किसानों की बकेटिंग का कार्य जल्द पूरा करने और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, एडीएम उमाशंकर बंदे, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम होने से नियुक्ति का अधिकार नहीं

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि केवल मेरिट सूची में नाम शामिल होने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का कानूनी रूप से अधिकार हासिल नहीं होता. सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि जब सक्षम प्राधिकारी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है, तो मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकता. मामला सूरजपुर जिले के रामानुजनगर का है. यहां की निवासी देवेन्द्र कुमारी साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिला पंचायत सूरजपुर ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत सचिव के 11 पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर 2018 को विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) वर्ग से आवेदन किया था और चयन प्रक्रिया के बाद उसका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल था.

सात साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने पर देवेन्द्र कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को पंचायत निदेशक से व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत कर यह बताने को कहा था कि वर्ष 2018 से भर्ती प्रक्रिया लंबित क्यों है. इसके जवाब में 3 नवंबर 2025 को पंचायत निदेशक ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जानकारी दी थी.राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2018 में जिला पंचायत सूरजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के लिए राज्य शासन और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी. इस कारण विज्ञापन नियमों के विपरीत और अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया था. पंचायत निदेशालय के 20 जनवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में जिला पंचायत सीईओ ने 22 अक्टूबर 2025 को पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था.

कन्या महाविद्यालय, देवेंद्र नगर में लक्ष्मी मिलेट कैफे का शुभारंभ

रायपुर। 29 जुलाई को संत गोबिंदराम शदाणी, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेंद्र नगर, रायपुर में ''लक्ष्मी मिलेट कैफे शुभारंभ'' समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री चन्द्रहास चन्द्राकर जी, अध्यक्ष बीज निगम छत्तीसगढ़, विशिष्ट अतिथि डॉ. अमिताभ बैनर्जी, अपर संचालक, उच्च शिक्षा/प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. गजेन्द्र चन्द्रकार, स्टेट नोडल ऑफिसर, साथी परियोजना एवं प्रिंसिपल साइंटिस्ट, कृषि विश्वविद्यालय एवं श्रीमती शताब्दी पांडे, पूर्व अध्यक्ष, महिला एवं बाल संस्थान आयोग की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में नाफ्रेड एवं साथी परियोजना के श्री अनुराग लाल जी एवं श्री संजय जोशी उपस्थित रहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. उषा किरण अग्रवाल जी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि श्री चन्द्रहास चन्द्राकर जी ने बताया कि आज के वातावरण एवं दिनचर्या में फास्ट फूड के अति उपयोग के कारण छोटे-छोटे बच्चों में मोटापा बढ़ है। अत: शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स के अधिक उपयोग पर जोर दिया। वैश्विक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलेट्स (श्री अन्न) देश के उन्नति एवं सभी के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। डॉ. गजेन्द्र चन्द्रकार ने बताया कि हमारे पूर्वज श्री अन्न के उपयोग एवं महत्ता जानते थे एवं उसका उपयोग करते थे। इसके उत्पादन के लिए कम पानी आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य के लिए उत्तम भोजन है। भविष्य में इसे सुपर फूड या फ्यूचर फूड के रूप में जाना जायेगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉ. अमिताभ बैनर्जी, अपर संचालक, उच्च शिक्षा ने विभाग द्वारा इस संदर्भ में किये गये कार्यों की जानकारी दी तथा बताया शासन इसे प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रहा है। श्रीमती शताब्दी पांडे द्वारा भी इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए मिलेट्स के अधिक से अधिक उपयोग के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित किया। प्राचार्य डॉ. उषा किरण अग्रवाल द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन की महत्ता बतलाते हुए इसके सफल होने के की कामना की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रवि शर्मा द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. आर.एस. लूका द्वारा किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में संत गोबिंदराम शदाणी, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेंद्र नगर, रायपुर के समस्त सम्माननीय प्राध्यापक गण एवं कर्मचारियों सहित छात्राएं उपस्थित रहें।

रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास की सराहनीय पहल, अंबेडकर अस्पताल में अब जरूरतमंदों को मिलेगा निशुल्क खाना

मेकाहरा में नि:शुल्क अन्न सेवा शुरूवात

रायपुर। सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास की पहल पर राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय परिसर में 'नि:शुल्क अन्न सेवाङ्क365 दिन' अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले जरूरतमंद परिजनों को पूरे वर्ष प्रतिदिन नि:शुल्क, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उपचार के दौरान उन्हें भोजन की चिंता न करनी पड़े। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास की इस जनहितैषी पहल का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। अभियान के संचालन में 'कुछ फर्ज हमारा भी' संस्था सहयोगी के रूप में जुड़ी है, जबकि रोटरी क्लब ऑफ रायपुर इन्फिनिटी सहयोगी संस्था एवं रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मोपॉलिटन समर्थक संस्था के रूप में इस सेवा अभियान का हिस्सा हैं। शुभारंभ के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वयं मरीजों के परिजनों को भोजन वितरित कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले अनेक परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे समय में भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था करना सबसे बड़ी मानव सेवा है। उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान केवल भोजन वितरण नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सामाजिक संवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और विश्वास है कि यह सेवा अभियान वर्षभर सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत और संबल का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि समाज की वास्तविक पहचान ऐसे सेवा कार्यों से होती है। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास ने जिस सोच, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ इस अभियान की शुरुआत की है, वह निश्चित रूप से अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो डिवास की अध्यक्ष नेहा जैन ने कहा कि इस अभियान की परिकल्पना लंबे समय से उनके मन में थी। उनका उद्देश्य था कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को कम से कम भोजन के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा कर उनसे मिलने वाली दुआएं ही सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से यह अभियान केवल 365 दिनों तक ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भी निरंतर चलता रहेगा और अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ पहुंचेगा।

संत रविदास की जयंती पर समरसता संकल्प अभियान फरवरी तक होंगे कई कार्यक्रम

रायपुर. छत्तीसगढ़ बीजेपी संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर प्रदेशभर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। यह कैंपेन 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक चलाया जायेगा। इस संबंध में प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि गुरु रविदास के दिखाया गया मार्ग ही हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प का मूल आधार है। उनके 650वें जयंती वर्ष पर चलने वाला समरसता संकल्प अभियान सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के निर्माण का जन आंदोलन बनेगा। इस अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास महाराज के समता, सामाजिक न्याय, मानवता, सेवा और सामाजिक समरसता के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना है। मंत्री वर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास केवल किसी एक समाज के संत नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के महान पथप्रदर्शक, भक्ति आंदोलन के महान संत, श्रेष्ठ समाज सुधारक और महान आध्यात्मिक चिंतक थे। उनके समय के अनेक संतों और बाद की पीढ़ियों के संतों ने भी सम्मान दिया। उन्होंने समाज के करोड़ों वंचित एवं उपेक्षित लोगों को सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन का उद्देश्य बताया। समानता और आत्मसम्मान का संदेश देकर करोड़ों लोगों के जीवन में नई चेतना जगाई। अभियान का शुभारंभ 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होगा।

उन्होंने कहा कि देशभर के सभी मंदिरों में गुरु रविदास महाराज समरसता दीप महोत्सव के तहत 51 हजार स्थानों पर दीप जलाये जायेंगे। इस कड़ी में 11 हजार दीप संत रविदास घाट वाराणसी में प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।

रैना बोले, अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से अच्छा फील्डर बना

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी बल्लेबाजी के साथ ही बेहतरीन फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। रैना के अनुसार अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से ही वह एक एक बेहतर फील्डिर बने थे। रैना का मानना है कि लगातार अभ्यास की एक मजबूत संस्कृति भारतीय क्रिकेट में हैं जिससे सभी को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए निर्धारित समय से आधा घंटा पहले मैदान पर पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके सत्र की शुरूआत हमेशा फील्डिंग से होती थी। यह आज की तरह मात्र कुछ कैच पकड़कर समाप्त होने वाला सत्र नहीं था, बल्कि इसमें हाई कैच, ग्राउंड फील्डिंग, स्लिप कैच और पैरेलल कैच जैसे विभिन्न अभ्यास शामिल होते थे। वह उत्तर प्रदेश में मोहम्मद कैफ के नेतृत्व को याद करते हैं, जो एक स्टंप लगाकर सीधे उस पर थ्रो करने का अभ्यास कराते थे और कहते थे, अगर सीधे स्टंप पर थ्रो नहीं मारोगे, तो अंतिम ग्यारह में जगह नहीं मिलेगी। इन्हीं कठिन और सटीक अभ्यास सत्रों ने उनकी फील्डिंग को मजबूत आधार दिया।

रैना की फील्डिंग को बेहतर बनाने में आदर्श खिलाड़ियों की टिप्स की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि जोंटी रोड्स जैसे महान फील्डर से तारीफ मिलना हमेशा खास होता है, क्योंकि वह हमेशा उनके आदर्श रहे हैं। भारत में उन्हें मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह से काफी प्रेरणा मिली। युवराज सिंह पॉइंट और कवर पर फील्डिंग करते थे, जबकि रैना मिड-ऑफ पर तैनात रहते थे। उनका लक्ष्य रहता था कि गेंद उनके बीच से न निकल पाए, जिससे भारतीय टीम के लिए एक मजबूत मध्य-फील्डिंग साझेदारी बनी।

रैना ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की एक डरावनी घटना को भी साझा किया, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी में इरफान पठान के साथ हुई थी। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और डेविड वॉर्नर ने स्वीप शॉट खेला, जिसमें गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उछल गई। रैना मिडविकेट पर थे और इरफान कैच पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे रैना ने बताया, मैं सिर्फ गेंद को देख रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इरफान कहां हैं। मुझे सिर्फ गेंद, फ्लडलाइट्स, दर्शक और पीछे लहराता तिरंगा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने कैच पूरा किया, उनकी जोरदार टक्कर इरफान पठान से हो गई। रैना ने कहा कि एक पल के लिए उन्हें लगा कि अगर उनका सिर इरफान के शरीर से टकराता तो गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन शुक्र है कि सिर्फ उनका कंधा टकराया और वे कैच पकड़ने में सफल रहे। हालांकि, इस टक्कर में इरफान पठान की पसली में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें काफी चोट आई। इस घटना से हमने एक बड़ी सीख ली कि जिसका कैच हो, उसे जोर से आवाज लगाकर बताना चाहिए।

इस घटना ने फील्डरों के बीच बेहतर संवाद की अहमियत को उनके मन में हमेशा के लिए बिठा दिया रैना ने निष्कर्ष निकाला कि शुरूआती वर्षों में मिला कठिन प्रशिक्षण, अनुभवी साथियों से मिली सीख और मैदान पर हुए ऐसे अनुभवों ने ही उन्हें एक ऐसा फील्डर बनाया, जिसकी फुर्ती, पूर्वानुमान क्षमता और समर्पण की लंबे समय तक प्रशंसा होती रही।

महत्वपूर्ण ख़बर

बुमराह अपनी फिटनेस बनाये रखने के लिए स्वयं उपाय करें : मैक्ग्रा

- मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी फिटनेस को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। उनके लगातार चोटिल होने का खतरा बना रहता है जिससे भारतीय टीम को भी नुकसान होता है। श्रीलंका के खिलाफ अगले माह होने वाली टेस्ट सीरीज में भी उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने कहा है कि बुमराह को अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। मैक्ग्रा ने कहा कि बुमराह को अपनी फिटनेस बनाये रखने और अपने करियर को लंबा करने का तरीका स्वयं तलाशना होगा।

मैक्ग्रा ने कहा, यह बुमराह पर ही निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। वे अभी युवा हैं, इसलिए उन्हें अपनी पारी को लंबा खींचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैक्ग्रा ने बुमराह की चोटों का जिक्र करते हुए उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज बताया। उन्होंने कहा कि बुमराह को यह तय करना होगा कि वे टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या सिर्फ टी20 खेलना चाहते हैं। यह उनके शरीर और गेंदबाजी एक्शन पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जो गेंदबाज अपनी बांह को अधिक खींचते हैं, वे उस जोड़ पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालते हैं।

भारतीय मूल के जय आयरलैंड से एकदिवसीय खेलते दिखेंगे

मुम्बई। भारतीय मूल के राजस्थान में जन्मे क्रिकेटर जय मूंदड़ा अब आयरलैंड क्रिकेट टीम से खेलते नजर आयेंगे। जय को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए आयरलैंड की एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है। जय का जन्म राजस्थान में हुआ था पर पढ़ाई के लिए वह आयरलैंड चले गए थे। जय का सपना क्रिकेटर बनना था जो अब पूरा होता दिख रहा है। कुछ समय पहले ही जय ने आयरलैंड की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही शानदार प्रदर्शन कर दो मैचों में 5 विकेट लिए थे, जिससे आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत हासिली की थी। इस प्रदर्शन के बल पर अब उन्हें एकदिवसीय टीम में जगह मिली है।

यदि जय अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में अपना वनडे डेब्यू करते हैं, तो वह आयरलैंड के लिए एकदिवसीय खेलने वाले दूसरे भारतीय मूल के क्रिकेटर बन जाएंगे। आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच 5 से 14 अगस्त के बीच पांच मुकाबलों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी। इसके शुरूआती तीन मुकाबलों के लिए आयरलैंड ने अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस सीरीज में कप्तान पॉल स्टर्लिंग भी वापसी कर रहे हैं, जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लगी चोट से उबर चुके हैं। जय मूंदड़ा के अलावा, बेन कैलिट्ज और बायरन मैकडोनो को भी उनके हालिया शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है। कैलिट्ज भी जय मूंदड़ा के साथ भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत का हिस्सा थे।

हालांकि, चोटों के कारण आयरलैंड को इस सीरीज में कई अनुभवी खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरना होगा। तेज गेंदबाज जोश लिटिल, मैट हॉलैंड, क्रेग यंग, बैरी मैकार्थी, जॉर्डन नील और डेविड डेलानी जैसे प्रमुख खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिससे टीम को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पांच मुकाबलों की यह एकदिवीसय सीरीज 5 अगस्त को ब्रेडी में शुरू होगी, जहां 7 अगस्त को दूसरा मैच भी खेला जाएगा। शेष तीन मुकाबले 10, 12 और 15 अगस्त को स्टॉर्मोंट में खेले जाएंगे। यह सीरीज नए नियुक्त हेड कोच गैरी विल्सन के लिए भी पहला महत्वपूर्ण असाइनमेंट होगी। पिछले दशक में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच सभी फॉर्मेट में कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है, जिसमें द्विपक्षीय क्रिकेट और आईसीसी इवेंट्स, दोनों में कई कड़े और यादगार मुकाबले देखे गए हैं, जिससे यह सीरीज भी रोमांचक होने की उम्मीद है। पांच मुकाबलों की एकदिवसीय डे सीरीज 5 अगस्त को ब्रेडी में शुरू होगी और दूसरा मैच भी 7 अगस्त को उसी वेन्यू पर खेला जाएगा. बाकी तीन मुकाबले 10, 12 और 15 अगस्त को स्टॉर्मोंट में खेले जाएंगे।

आशुतोष के नाम है घरेलू क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकार्ड

मुम्बई। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक की बात करे तो अधिकतर प्रशंसकों की नजरें आक्रामक ऑलराउंडर युवराज सिंह की ओर जाती हैं पर ये सही नहीं घरेलू क्रिकेट में ये रिकार्ड युवराज नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा के नाम है। आशुतोष ने साल 2023 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवे की ओर से खेलते हुए यह ऐतिहासिक रिकार्ड अपने नाम किया था। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में आशुतोष ने केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया जबकि युवराज ने 12 गेंदों में ये कारनामा किया था। इस के साथ ही आशुतोष भारत के लिए सबसे तेज टी20 अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। इस पारी के दौरान आशुतोष ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्के लगाये जिससे विरोधी गेंदबाजों को कोई अवसर नहीं मिला। उनकी इस विस्फोटक पारी से रेलवे ने एक विशाल स्कोर बनाया। उनकी यह पारी टी20 फॉर्मेट की तेजी और अनिश्चितता का बेहतरीन उदाहरण है, जहां कोई भी बल्लेबाज किसी भी पल मैच का रुख पलट सकता है। हालांकि, अगर पूरे टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक के विश्व रिकॉर्ड की बात करें, तो वह नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम दर्ज है। उन्होंने साल 2023 में एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में पचास रन बनकार सभी को हैरान कर दिया था। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल थी। दीपेंद्र का यह रिकॉर्ड आज भी बना हुआ है और इसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दीपेंद्र और आशुतोष ने भले ही युवराज से कम गेंदों में टी20 फिफ्टी जमाई हो, लेकिन युवराज की 12 गेंदों की पारी आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार और प्रतिष्ठित पारियों में गिनी जाती है। 2007 टी20 विश्व कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार छह छक्के लगान और उसी दौरान टी20 अंतराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक पूरा करना, यह ऐसा करिश्मा था जिसने क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया था। युवराज का यह रिकॉर्ड लंबे समय तक टी20 अंतरराष्ट्रीय में बना रहो।

एशेज में वापसी कर सकते हैं स्टोक्स: मैकडोनाल्ड

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच एंड्र्यू मैकडोनाल्ड ने दावा किया है कि हाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स अगले साल होने वाली एशेज सीरीज में वापसी कर सकते हैं।

स्टोक्स ने पिछले महीने न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद अचानक ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनके टीम में नहीं रहने से इंग्लैंड को करारा झटका लगा है। मैकडोनाल्ड ने हालांकि कहा कि कि उनके पास स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है पर उनका आंकलन है कि इंग्लैंड प्रबंधन इस पूर्व कप्तान को वापसी के लिए मनाएगा। इसलिए अगर स्टोक्स एशेज 2027 के लिए वापसी करते हैं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियाई कोच ने कहा, अगर वह संन्यास से वापसी करें और एक और एशेज खेलें, तो यह अच्छा रहेगा। उसकी वापसी काफी चचाओं में रहेगी। उन्होंने साथ ही कहा, अगर आप उस सीरीज रोमांच बनाना चाहते हैं, तो शायद आप यही चाहेंगे कि वह संन्यास से वापसी करें।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं होगा जब स्टोक्स ने संन्यास से वापसी की हो। 2022 में, वह इंग्लैंड के लिए 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेलने के लिए एकदिवसीय से वापस लौटे थे पर टीम अपना खिताब बचाने में असफल रही थी। स्टोक्स अभी इंग्लैंड की घरेलू 50-ओवर प्रतियोगिता में डरहम के लिए खेल रहे हैं, जहां उन्होंने लगातार नाबाद 108 और 73 रन की प्रभावशाली पारियां खेली हैं। हालांकि, हाल ही में स्टोक्स ने संकेत दिया था कि भविष्य में टीम प्रबंधन द्वारा संपर्क किए जाने पर भी वह वापसी नहीं करेंगे।

...और द ओवल में टेस्ट मैच होंगे

उनके संन्यास के बाद इंग्लैंड के टेस्ट सेटअप को लेकर संशय बरकरार है। मैकडोनाल्ड ने स्वीकार किया कि वह अगली एशेज सीरीज से पहले हो रही गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। मैकडोनाल्ड का मानना है कि स्टोक्स में अभी भी काफी अच्छी क्रिकेट बाकी है। उन्होंने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि जो भी नया मुख्य कोच आएगा, वह शायद उनसे बातचीत करेगा। ऑस्ट्रेलियाई कोच ने स्टोक्स के संन्यास के सटीक कारण पर भी अनिश्चितता व्यक्त की। हमें नहीं पता कि बेन क्यों चले गए, मुझे नहीं लगता कि उनके जाने के पक्के कारण के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। इस बीच, इंग्लैंड ने हाल ही में एशेज 2027 का शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में 18 जून से पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिसके बाद लॉर्ड्स, एजबेस्टन, द रोज बाउल और द ओवल में टेस्ट मैच होंगे।

कारोबार

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच शेयर बाजार की कमजोर शुरूआत, सेंसेक्स 115 अंक गिरा, निफ्टी भी टूटा

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है. जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा जा रहा है. बुधवार शाम अमेरिका ने ईरान पर दोबारा से हमले शुरू कर दिए. इसके बाद गुरुवार को खुले भारतीय शेयर बाजार की शुरूआत गिरावट का साथ हुई.

बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ खुले. शुरूआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (इरए) पर सेंसेक्स 115 अंक गिर गया. जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ठरए) पर निफ्टी50 में 35 अंकों में की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त उछाल के साथ खुला था.

कैसी रही बाजार की शुरूआत?

आज यानी गुरुवार (30 जुलाई) को भारतीय शेयर बाजार की शुरूआत गिरावट के साथ हुई. गुरुवार सुबह बीएसई का सेंसेक्स 84.26 अंक की मामूली गिरावट के साथ 77638.86 पर खुला, जो बुधवार को 77654.60 के स्तर पर बंद हुआ था. सुबह 9.50 बजे तक सेंसेक्स 77737.22 अंक के उच्चतर स्तर और 77440.91 के निचले स्तर पर कारोबार करता दिखा. जबकि एनएसई का निफ्टी50, 24249.55 के स्तर पर ओपन हुआ. जो बुधवार (29 जुलाई) को 24250.20 अंक पर बंद हुआ था. इस दौरान निफ्टी 24287.25 के उच्च स्तर और 24187.10 के निचले स्तर पर ट्रेड करता दिखा.

गिरावट के बाद बाजार में दिखी तेजी, क्ळ शेयरों से मिला सपोर्ट

शेयर बाजार की शुरूआत आज भले ही गिरावट के साथ हुई हो लेकिन आईटी शेयरों बाजार को सपोर्ट किया और निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी के चलते बाजार में फिर से तेजी देखने को मिली. शुरूआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 75.71 अंक की बढ़त के साथ 77,726.62 पर पहुंच गया. जबकि ठरए का 50 शेयरों वाला निफ्टी 26.90 अंक बढ़कर 24,275.85 पर कारोबार करता दिखा. शुरूआती कारोबार में जिन कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई उनमें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (ळउर) शामिल रही. इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा के शेयरों में भी उछाल दर्ज किया गया. जबकि दूसरी ओर, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, एटरनल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में आज गिरावट देखी जा रही है. जो बाजार की बढ़त को थोड़ा सीमित कर रहे हैं.

विदेशी निवेशकों का लौटा बाजार पर भरोसा

शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (त्र्क्र) की ओर से घरेलू बाजार में लगातार निवेश किया जा रहा है. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, बुधवार को विदेशी निवेशकों ने 2,981.87 करोड़ मूल्य के शेयरों की खरीदारी की. वहीं ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों में गिरावट के चलते भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड गुरुवार को 1.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 89.60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे इंडियन इकॉनोमी और मार्केट को बड़ी राहत मिली है.

वैश्विक बाजारों में भी दिखा मिला-जुला असर

गुरुवार को वैश्विक बाजारों में भी मिला जुला असर देखने को मिला. आज सुबह एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे, जबकि जापान का निक्केई ग्रीन जोन में ट्रेड करता नजर आया.

दिल्ली-एनसीआर में नेशनल के बजाय लोकल डेवलपर्स का अभी भी दबदबा!

नई दिल्ली। एनारॉक रिसर्च के ताजा रिपोर्ट सामने सामने आई है. रिसर्च के अनुसार, एनसीआर में नेशनल डेवलपर्स की नई रेजिडेंशियल सप्लाई 2022 के 3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 के अंत तक 13 प्रतिशत से अधिक हो गई है. गोदरेज, प्रेस्टीज, टाटा हाउसिंग, महिंद्रा, अडानी, सोभा और बिड़ला जैसे बड़े राष्ट्रीय डेवलपर ब्रैंड तेजी से विस्तार कर रहे हैं. इसके बावजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोकल डेवलपर्स का दबदबा कायम है.

गुरुग्राम में राष्ट्रीय डेवलपर्स की नई सप्लाई का 47 प्रतिशत हिस्सा केंद्रित है, जबकि नोएडा की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत और ग्रेटर नोएडा की करीब 12 प्रतिशत है. यह दिखाता है कि इस बेल्ट में उनकी पकड़ अभी सीमित है और क्षेत्रीय डेवलपर्स का प्रभाव ज्यादा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय डेवलपर्स का असली लाभ उनकी माइक्रो मार्केट पर गहरी पकड़, मजबूत ग्राहक आधार व नेटवर्क, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और पुराने दरों पर अधिगृहीत भूखंड है. इसके अलावा क्षेत्रीय डेवलपर्स द्वारा समय की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण और विकास हेतु नई और विकसित तकनीक अपनाई जा रही एवं अलग अलग-अलग थीम, कान्सेप्ट के साथ परियोजना में विशेषताएं व सुविधाएं दी जा रही है जिसके लिए राष्ट्रीय डेवलपर्स जाने जाते है. एक तरफ क्षेत्रीय डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग से ऊपर बढ़कर लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं और कीमत काफी प्रतिस्पर्धी रख रहे है. दूसरी तरफ नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में एंड-यूजर्स होने के कारण खरीदार ब्रैंड से ज्यादा समय पर पजेशन, अफोर्डेबल कीमत पर राष्ट्रीय स्तर वाली गुणवत्ता और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड तथा ट्राइड एण्ड टेसटेड यानि इस्तेमाल के बाद विश्वास किए जाने वाले पुराने ग्राहक उन्हीं क्षेत्रीय डेवलपर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं.

हालांकि राष्ट्रीय डेवलपर्स के आने से परियोजनाओं की डिजाइन, निर्माण तकनीक, ग्राहक पारदर्शिता और योजना प्रबंधन बेहतर हुए हैं. इससे पूरे सेक्टर में प्रतियोगिता बढ़ी है और क्षेत्रीय डेवलपर्स पर भी हरित भवन विकास, निर्माण स्तर और समयबद्ध पूर्णता के मानक सुधारने का दबाव बढ़ा है. इस कारण रियल एस्टेट सेक्टर में चौतरफा सुधार हुआ है जो घर खरीदारों सहित अन्य हितधारकों के हित में है.

31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो क्या होगा

नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जल्द कर लें। 31 जुलाई 2026 आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है, जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती। समय पर आईटीआर भरने से आपका टैक्स रिकॉर्ड सही रहता है, ज्यादा कटा हुआ टैक्स वापस (रिफंड) मिल सकता है और बाद में जुमानें जैसी परेशानी से बचा जा सकता है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि यह आखिरी तारीख किसके लिए है? किन लोगों के लिए इसे भरना जरूरी है? कौन से दस्तावेज जरूरी है? कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? फॉर्म भरने का तरीका क्या-क्या है? अगर आईटीआर नहीं भरा तो क्या होगा? आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। यह एक फॉर्म होता है, जिसके जरिए आप आयकर विभाग को बताते हैं कि पूरे साल आपकी कितनी कमाई हुई, उस पर कितना टैक्स कटा या जमा हुआ और अगर ज्यादा टैक्स कट गया है तो उसका रिफंड भी इसी प्रक्रिया के जरिए मिलता है।

ऐसे करदाता जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं?

अगर आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है और आप ITR-3 या ITR-4 भरते हैं, तो आपके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है।

किन लोगों के लिए आईटीआर भरना जरूरी है?

इन लोगों को आईटीआर जरूर दाखिल करना चाहिए; जिनके पास भारत या विदेश में कोई मकान, जमीन या दूसरी अचल संपत्ति है। जिन्होंने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या ईएसओपी में निवेश किया है। जिनके बैंक खातों में तय सीमा से ज्यादा नकदी जमा हुई है। जिनका सालाना बिजली बिल एक लाख रुपये से ज्यादा है। जिन्होंने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है। जिनके कारोबार का सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपये से ज्यादा है।

महत्वपूर्ण ख़बर

अद्वितीय है महर्षि सांदीपनि आश्रम : सीएम

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम अत्यंत गौरवशाली और अद्वितीय है। लगभग 5100 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने इसी पावन स्थल पर महर्षि सांदीपनि से विद्या ग्रहण की थी। भगवान श्रीकृष्ण से शिक्षा प्राप्त कर जगद्गुरु की उपाधि से विभूषित हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उज्जैन के प्रमुख देवस्थानों के विकास कार्यों का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें शहर को गीता भवन की बड़ी सौगात भी मिल रही है।

ग्वालियर बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब

लगभग 15 हजार करोड़ रुपए निवेश और 5 हजार रोजगार होगा सृजन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। संचार मंत्रालय एवं दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के तहत ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन एवं दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के बीच प्रस्तावित एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह एमओयू परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन कंपनी के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा और देश में दूरसंचार विनिर्माण के नए युग की शुरूआत करेगा।

लगभग 350 एकड़ में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्लस्टर मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर तथा 5जी और 6जी अनुसंधान एवं विकास सहित दूरसंचार क्षेत्र की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही परिसर में विकसित करेगा। इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए भारत सरकार ने 493 करोड़ रुपए का शत-प्रतिशत केंद्रीय अनुदान स्वीकृत किया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा सडा क्षेत्र में 100 एकड़ तथा ग्वालियर आईटी पार्क में 70 एकड़, कुल 170 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 596 करोड़ रुपए है। परियोजना के अंतर्गत सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाएं, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, आधुनिक भण्डारण, सड़क तथा आईसीटी जैसी साझा अधोसंरचना भी विकसित की जाएगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से आगामी वर्षों में लगभग 12 हजार से 15 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है तथा लगभग 5 हजार प्रत्यक्ष कुशल रोजगार सृजित होंगे। इनमें से करीब 3,500 रोजगार प्रथम चरण में ही उपलब्ध होने का अनुमान है। यह परियोजना राउटर, एंटीना, ऑप्टिकल फाइबर, चिप तथा अन्य दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करेगी और निर्यात को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एचएफसीएल, तेजस नेटवर्क्स, वीवीडीएन तथा सिरमा एसजीएस जैसी अग्रणी दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां एंकर निवेशक के रूप में जुड़ रही हैं। प्रारंभिक प्रतिबद्धताओं के अनुसार प्रथम चरण में 150 से 200 एकड़ क्षेत्र में लगभग . 5 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। परियोजना का संचालन विशेष प्रयोजन कंपनी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश शासन की 51 प्रतिशत तथा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी होगी।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को देश के सबसे आकर्षक औद्योगिक निवेश स्थलों में विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत पात्र स्थिर पूंजी निवेश पर अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान, मेगा परियोजनाओं के लिए रोजगार सृजन सहायता, प्रत्येक नए कर्मचारी के कौशल विकास पर वित्तीय सहायता, मात्र 1 रुपए प्रीमियम पर भूमि आवंटन तथा 30 वर्षों तक नाममात्र की लीज दर का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रारंभिक पांच वर्षों तक विद्युत टैरिफ में प्रति यूनिट रु. 2 की छूट, मालभाड़ा सब्सिडी, अनुसंधान एवं विकास सहायता, पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा व्यय की प्रतिपूर्ति तथा हरित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाले विशेष प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे। यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन तथा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनुसंधान से लेकर कंपोनेंट निर्माण और अंतिम उत्पाद निर्माण तक की सम्पूर्ण श्रृंखला को एकीकृत करेगी। साथ ही एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्थानीय आपूर्तिकताओं को बड़े उद्योगों के साथ विकसित होने का अवसर मिलेगा, जिससे देश की दूरसंचार सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी। प्रस्तावित एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ ही ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह परियोजना मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी।

छह साल बाद मिला इंसाफ, इंदौर शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में तीन हत्यारों को उम्रकैद

इंदौर। शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है।

वारदात 2 सितंबर 2020 को हुई थी। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में आने वाले उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में लूट की नियत से घूसे आरोपियों ने रेस्टोरेंट मालिक रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने साहू की पत्नी

गीता और बेटी जया के साथ मारपीट की और गहने लूटकर भाग निकले।

आठ आरोपियों को किया था गिरफ्तार

8 आरोपियों को किया था गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में जांच के बाद धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के गांव लोहार निवासी विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान, प्रेम सिंह सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छह साल चले प्रकरण में अभियोजन ने गीता और जया सहित कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। बुधवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेमसिंह के विरुद्ध हत्या का दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इंदौर में दूषित पानी से बढ़ा बीमारी का खतरा

नर्मदा लाइन से आ रहा काला पानी; सैकड़ों परिवार परेशान

इंदौर। मूसाखेड़ी क्षेत्र की अजय बाग कॉलोनी के रहवासी पिछले दो माह से दूषित पेयजल की समस्या का सामना कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि नर्मदा जल सप्लाई वाले दिन नलों से शुरूआती 15 से 20 मिनट तक काला और बदबूदार पानी निकलता है। पानी से सीवेज जैसी दुर्गंध आती है, जिसके कारण लोग इसे घरेलू उपयोग में लेने से भी डर रहे हैं। उनका कहना है कि दूषित पानी के कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है और कई लोग बीमार भी हो चुके हैं।

पीने के लिए खरीदना पड़ रहा पानी

कॉलोनी के अधिकांश परिवार पीने के पानी के लिए नर्मदा जल सप्लाई पर निर्भर हैं। हालांकि कुछ घरों में बोरिंग की सुविधा है, लेकिन दूषित पानी आने से कई परिवारों को बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है। रहवासियों ने सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम के 311 एप पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि बिना समाधान किए शिकायतों का निराकरण दिखा दिया गया।

पुरानी पाइपलाइन पर जताई आशंका

रहवासियों के अनुसार, इस समस्या की शिकायत दो माह पहले जोनल कार्यालय में भी की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच के लिए निगम के कर्मचारी पहुंचे, मगर इसके बाद दोबारा नहीं आए। लोगों ने आशंका जताई कि भागीरथपुरा की तरह अजय बाग में भी जल वितरण लाइन में सीवरेज का पानी मिल रहा है। उनका कहना है कि पाइपलाइन काफी पुरानी है और निर्माण कार्यों के दौरान कई बार खुदाई होने से भी समस्या बढ़ी हो सकती है। रहवासियों ने नगर निगम से स्थायी समाधान की मांग की है। वहीं, जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा ने शिकायत की जांच कराने की बात कही है।

सरकारी जमीन पर 'न्यू लक्ष्मी नगर' का खेल खत्म, 40 करोड़ की भूमि पर चला बुलडोजर; भूमाफिया अज्जू गिरफ्तार

इंदौर। शासकीय भूमि पर अवैध कालोनियां बसाने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्हारगंज तहसील के ग्राम सिरपुर में करीब 40 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। मुख्य आरोपित अज्जू खां के खिलाफ चंदननगर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। वहीं पूछताछ में सामने आए मास्टरमाइंड जफर खान की पुलिस तलाश कर रही है।

मल्हारगंज एसडीएम निधि वर्मा को सूचना मिली थी कि ग्राम सिरपुर के सर्वे क्रमांक 33 की 2.711 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसाई जा रही है। जांच में यह भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के नाम दर्ज मिली। इसके बावजूद भूमाफिया अज्जू खां इसे अपनी निजी जमीन बताकर 'न्यू लक्ष्मी नगर' नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर रहा

था। जांच में सामने आया कि आरोपित ने सरकारी जमीन के 100 से अधिक प्लॉट काटकर करीब पांच लाख रुपये प्रति प्लॉट की दर से नोटरी के माध्यम से बेच दिए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार पांच करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की जा चुकी है। सर्वे क्रमांक 37/1 की भूमि को भी आरोपित अपनी बताकर बेचने का प्रयास कर रहा था, जबकि उसका स्वामित्व भी उसके नाम नहीं है।

कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि पर बने टीनशेड मकानों में रह रही जरीना बी, बबली और यास्मीन मंसूरी के खिलाफ राजस्व प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश जारी किए गए। राजस्व, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जेसीबी और बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाकर भूमि को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

चंदननगर पुलिस के अनुसार पूछताछ में अज्जू खां ने बताया कि उसका जीजा जफर खान पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। उसने दलाल जावेद की मदद से प्लॉट बेचवाए। पुलिस ने आरोपितों के बैंक खातों की जानकारी भी मांगी है। प्रशासन अब उन सभी लोगों की जानकारी जुटा रहा है जिन्होंने ये प्लॉट खरीदे हैं। दलालों और पूरे नेटवर्क की भी जांच की जाएगी।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि चार मई को भी प्रशासन ने इसी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर की गई फेंसिंग और अस्थायी निर्माण हटाए थे। चेतावनी के बावजूद दोबारा अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास सामने आने पर इस बार एफआइआर, बेदखली और बुलडोजर कार्रवाई एक साथ की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार जिलेभर में शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने और अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।

2 घंटे सड़क पर तड़पता रहा घायल, न पुलिस पहुंची न एम्बुलेंस

शव के पास धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता

रन्नौद। शिवपुरी जिले के रन्नौद थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद एक घायल व्यक्ति दो घंटे तक सड़क किनारे तड़पता रहा, लेकिन न तो वक्त पर पुलिस पहुंची और न ही कोई एम्बुलेंस। हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी घायल/शव को तुरंत अस्पताल भिजवाने की जगह उसे चुनावी मुद्दा बनाकर सड़क पर धरना शुरू कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 4 बजे खरैह निवासी 55 वर्षीय जगदीश जोशी (पिता भगवान लाल जोशी) अपनी बाइक से सजाई मार्ग होकर वापस गांव लौट रहे थे। खरैह में स्थित पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे के बाद पुलिस केस के डर से मौके पर मौजूद किसी भी राहगीर या ग्रामीण ने घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस मामले में

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय रघुवंशी का आरोप है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद रन्नौद थाना प्रभारी, एसडीएम (रऊट) और तहसीलदार सभी को कई बार फोन मिलाया। लेकिन एक घंटे से अधिक समय तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या डायल-100 मौके पर नहीं पहुंची। करीब दो घंटे तक जब कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची, तो आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण शव के पास ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस अध्यक्ष विजय रघुवंशी का कहना है कि रन्नौद पुलिस की घोर लापरवाही के कारण समय पर इलाज न मिलने से व्यक्ति की जान चली गई। मृतक को न्याय दिलाने के लिए वे धरने पर बैठने को मजबूर हुए। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि यदि हादसे के तुरंत बाद बहसबाजी और राजनीति की जगह व्यक्ति को किसी भी वाहन से अस्पताल पहुंचा दिया जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी।

कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस से बहस अपराध नहीं

इंदौर। विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) ने आगर-मालवा जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र में शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित आठ आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधि या आम नागरिक का पुलिस अधिकारियों से बहस या तर्क-वितर्क करना मात्र शासकीय कार्य में बाधा का अपराध नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह साबित होना आवश्यक है कि लोक सेवक पर हमला किया गया हो या उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और पूरे घटनाक्रम का विस्तृत परीक्षण किया। पर्याप्त और स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सभी आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।

दो बेटियों के जन्म और दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी, पति समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज

ग्वालियर। ग्वालियर में लगातार दो बेटियों को जन्म देने पर ससुराल वालों ने एक महिला से दहेज की मांग की। उन्होंने मारपीट और 25 लाख रुपए/क्रेटा कार मांगा, जिससे तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के कुंअरपुर गांव की है। पुलिस ने मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या समेत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

मुरैना (जौरा) निवासी मेहताब सिंह सिकरवार ने अपनी बेटी ज्योति की शादी महाराजपुरा के कुंअरपुर निवासी शुभम सिंह राजावत से की थी। शादी के कुछ समय बाद ज्योति ने पहली बेटी को जन्म दिया और डेढ़ साल बाद दूसरी बेटी का जन्म हुआ। बेटा न होने पर पति और ससुराल वाले ज्योति को दिन-रात ताने देने लगे। आरोप है कि उसके साथ घर में मारपीट की जाती थी और कई बार खाना तक नहीं दिया जाता था।

मायके पक्ष के बयान के मुताबिक- बेटियों के जन्म के बाद ससुराल वालों का लालच और बढ़ गया। वे ज्योति से दहेज में क्रेटा कार या 25 लाख नकद की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे कई बार घर से बाहर निकाल दिया गया। पति शराब के नशे में उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। इस प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति ने 9 जुलाई को अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद महाराजपुरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। मायके पक्ष के बयान दर्ज होने के बाद प्रताड़ना और दहेज की खौफनाक कहानी सामने आई। इसके आधार पर पुलिस ने पति शुभम सिंह राजावत, ससुर चंद्रभान राजावत, सास सरकली राजावत, सौरभ राजावत, रोहित राजावत, दीपक राजावत, सलोनी राजावत और शिवानी राजावत के खिलाफ दहेज हत्या और प्रताड़ना की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

एमपी में रेलवे की बड़ी सौगात...कटनी में देश का सबसे लंबा रेल ग्रेड सेपरेटर तैयार, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत कटनी में निमार्णाधीन देश के सबसे लंबे रेल ग्रेड सेपरेटर (रेल फ्लाईओवर) को वर्ष 2026 के अंत तक परिचालन के लिए तैयार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित की जा रही 33.40 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। रेलवे ने नवंबर तक शेष निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि वर्षांत तक पूरे ग्रेड सेपरेटर पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सके।

करीब 1800 करोड़ रुपये की लागत से कटंगी खुर्द से न्यू मझगवां तक विकसित हो रही इस परियोजना में 15.85 किलोमीटर लंबा अप ट्रैक पहले ही चालू किया जा चुका है। इस ट्रैक पर वर्तमान में प्रतिदिन 20 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन हो रहा है। वहीं 17.52 किलोमीटर लंबे डाउन ट्रैक का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वायडक्ट आधारित यह डाउन ट्रैक भारतीय रेलवे की सबसे लंबी एलिवेटेड रेल संरचनाओं में शामिल होगा।

कटनी यार्ड पर घटेगा दबाव, ट्रेनों को मिलेगी सीधी राह

परियोजना पूरी होने के बाद

बिलासपुर और सिंगरौली की दिशा से आने वाली तेज रफ्तार यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां कटनी जंक्शन, न्यू कटनी जंक्शन तथा कटनी मुड़वारा यार्ड में प्रवेश किए बिना सीधे बीना-दमोह-सागर रेलखंड की ओर रवाना हो सकेंगी। इससे कटनी के व्यस्त रेलवे यार्ड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही यात्री ट्रेनों का संचालन अधिक समयबद्ध और सुचारु होने के साथ मालगाड़ियों की संख्या एवं गति में भी वृद्धि होगी।

तकनीकी चुनौतियों से प्रभावित हुआ डाउन ट्रैक का निर्माण

रेलवे के अनुसार डाउन ट्रैक का निर्माण पहले ही पूरा होना था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और निर्माण संबंधी जटिलताओं के कारण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। इस परियोजना की समय सीमा दो से तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। कटनी मुड़वारा यार्ड के ऊपर वायडक्ट निर्माण के दौरान गर्डर लांचिंग सहित कई महत्वपूर्ण सिविल इंजीनियरिंग कार्य अभी बाकी हैं।

पश्चिम मध्य रेल के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर शेष कार्य को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। लक्ष्य है कि नवंबर तक निर्माण पूरा कर वर्षांत तक ट्रैक को परिचालन के लिए तैयार कर दिया जाए।

अप लाइन से पहले ही मिल रहे सकारात्मक परिणाम

परियोजना की 15.85 किलोमीटर लंबी अप लाइन का निर्माण गत वर्ष पूरा हुआ था। कोरोना काल के दौरान निर्माण कार्य प्रभावित होने से यह ट्रैक भी निर्धारित समय पर तैयार नहीं हो सका था। हालांकि इसके शुरू होने के बाद मालगाड़ियों का संचालन अधिक व्यवस्थित हुआ है और ट्रेनों का होल्डिंग टाइम कम हुआ है। कटनी में पांच दिशाओं से ट्रेनों की आवाजाही होने के कारण यार्ड और आउटर पर ट्रेनों को लंबे समय तक रोकना पड़ता था। डाउन लाइन के चालू होने के बाद मालगाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ सकेंगी।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।